@Kamal.Sandesh KamalSandeshLive www.kamalsandesh.org kamal.sandesh @KamalSandesh

कमल संदेश

'शिरोमणि अकाली दल और भाजपा राजग को मजबूत करने में लगे हुए हैं'

वर्ष-15, अंक-05 01-15 मार्च, 2020 (पाक्षिक) ₹20

अंत्योदय के लिए काम कर रहा है 21वीं सदी का भारत

पटना (बिहार) में प्रदेश भाजपा कार्यालय से 11 नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, साथ में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेंद्र यादव व अन्य वरिष्ठ नेतागण

अमृतसर (पंजाब) में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा का शानदार स्वागत करते पंजाब भाजपा कार्यकर्तागण

नई दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वैंकेया नायडु से शिष्टाचार मुलाकात करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा

ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) में 34वें राज्य स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह

रांची (झारखंड) में भाजपा-झारखंड विकास मोर्चा 'मिलन समारोह' में जनाभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमितशाह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी व अन्य

स्टॉकहोम (स्वीडन) में 'सड़क सुरक्षा' पर तीसरे उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

ई-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 1250 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में 16 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया और दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने तीन ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों-वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ने वाली तीसरी कार्पोरेट ट्रेन–महाकाल एक्सप्रेस...

वैचारिकी

आत्मिक सुख की आवश्यकता 15

श्रद्धांजलि

भारत रत्न नानाजी देशमुख 18

अन्य

मध्यप्रदेश, सिक्किम, केरल, महाराष्ट्र एवं मुंबई में नए प्रदेश भाजपा 08

भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाः आईएमएफ 12

2019-20 के लिए 291.95 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन... 13

'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना के पांच वर्ष पूरे 14

आर्थिक मोर्चे पर भारत का यह लाजवाब प्रदर्शन और सुनहरे भविष्य... 19

शिरोमणि अकाली दल और भाजपा राजग को मजबूत करने में लगे... 21

10,000 नए एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन हेतु 'कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन' को मंजूरी 24

भारतीयों ने महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का खुले दिल से स्वागत... 25

धारा 371 को कोई हटा नहीं सकता, न ही ऐसी कोई मंशा... 27

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत वितरित हो चुके हैं... 28

प्रधानमंत्री का हुनर हाट जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने का अनुरोध 30

'हुनर हाट' देखने पहुंचे प्रधानमंत्री 32

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से की मुलाक़ात और अयोध्या आने का दिया निमंत्रण 33

10 भारतीय जनता पार्टी 'विकास' की पर्यायवाची बन गई है...

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 फरवरी को बिहार प्रदेश...

11 हमने विकासवाद को राजनीति का आधार बनाया और सत्ता को सेवा...

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 फरवरी को नवी मुंबई में महाराष्ट्र राज्य भाजपा परिषद्...

23 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-दो को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के दूसरे...

26 खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स में 80 में से 56 रिकॉर्ड हमारी बेटियों के नाम...

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी को ओडिशा में वीडियो लिंक के माध्यम से पहले...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

नरेन्द्र मोदी

देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, बल्कि एक-एक नागरिक के संस्कार से बनता है। नागरिक के संस्कार को उसकी कर्तव्य भावना श्रेष्ठ बनाती है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण ही भारत के भविष्य को तय करेगा, नए भारत की दिशा तय करेगा।

अमित शाह

पं. दीनदयाल उपाध्याय जी ऐसे युगद्रष्टा थे, जिन्होंने देश को एक ऐसी विचारधारा देने का काम किया जिसका मूल उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करना हो। पंडित जी ने देश को एकात्म मानव दर्शन दिया, जिसमें व्यक्ति से समष्टि तक सभी के हित समाहित हैं।

नितिन गडकरी

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए युवाओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।

पीएमईजीपी योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में विशेष श्रेणी के लोगों को 25% अनुदान दिया जा रहा है।

facebook

गत 5 वर्षों में बिहार ने विकास के नए आयामों को देखा है। हम समाज के सभी वर्गों में केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को पहुंचाने में सफल रहे हैं। हमें यहां हुए अभूतपूर्व विकास को जनता के बीच लेकर जाना है।

— जगत प्रकाश नड्डा

राजस्थान सरकार का फोकस विकास पर नहीं, बल्कि हमारी भाजपा सरकार की योजनाओं का नाम बदल कर जनता को गुमराह करने पर है। बजट में भामाशाह कार्ड को जन आधार कार्ड, स्वस्थ राजस्थान को निरोगी राजस्थान, पीएमकेवीवाई को सीएमकेवीवाई का नाम देकर सरकार लोगों को भ्रमित करने का असफल प्रयास कर रही है।

—वसुंधरा राजे

सीएए के विरोध के नाम पर इस पागलपन को देखें... बेंगलुरु में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ एक वामपंथी कार्यकर्ता... इस बदनुमा दाग ने विरोध प्रदर्शन पर कब्जा कर लिया है। समय आ गया है जब कहा जाए 'बहुत हुआ।'

— बी.एल. संतोष

भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था

विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भारत ने पुनः एक शानदार उपलब्धि प्राप्त की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं सुदृढ़ नेतृत्व में भारत उपलब्धियों का अंबार लगा रहा है तथा राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी नयी ऊर्जा, शक्ति एवं आकांक्षाओं के पंख लगाकर देश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। देश को आगे ले जाने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता, नई कार्य–संस्कृति तथा हर मोर्चे पर देश के लिए उत्कृष्ट उपलब्धियों के रूप में देखा जा सकता है। जब से मोदी सरकार केंद्र में आयी है, परिणाम अत्यंत उत्साहवर्द्धक रहे हैं तथा हर क्षेत्र में देश नए–नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जिससे जन–जन के मन में आशा की किरण का संचार हुआ है। एक नया भारत, अपनी नई यात्रा एक गौरवशाली भविष्य के लिए शुरू कर चुका है।

विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हर भारतीय को गर्व हो रहा है। भारत अब 2.94 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर इंग्लैंड एवं फ्रांस को पीछे छोड़ चुका है। यह एक ऐसा स्थान है जिस पर भारत निर्णायक रूप से स्थापित हो चुका है और यदि अर्थशास्त्रियों की मानें तो आने वाले वर्षों में भारत और भी ऊंचे पायदानों पर दिखाई देगा। यह बहुत पुरानी बात नहीं है कि जब 2010 में भारत नौंवे स्थान पर था और मात्र नौ वर्षों में भारत अब पांचवें स्थान तक की यात्रा कर चुका है। पिछले पांच वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़ा है तथा विश्व आर्थिक परिदृश्य में अपने बढ़ते हुए कद का अहसास दिलाया हैं। अब जबकि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने को कृतसंकल्पित है, आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था और भी अधिक सुदृढ़ होकर विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) में भारत 10.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के रूप में पहले से ही विश्व में अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। जहां तक नॉमिनल जीडीपी का प्रश्न है, भारत अब अमेरिका, चीन, जापान एवं जर्मनी के बाद पांचवें स्थान पर है। आने वाले वर्षों में जैसे–जैसे भारत पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के करीब पहुंचता जाएगा, इसके कदम विश्व में और अधिक ऊंचे पायदान की ओर बढ़ेंगे।

विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हर भारतीय को गर्व हो रहा है। भारत अब 2.94 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर इंग्लैंड एवं फ्रांस को पीछे छोड़ चुका है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 'रिफॉर्म, परफॉर्म एवं 'ट्रांसफॉर्म' के एक युग की शुरुआत कर भारत ने पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 'अंत्योदय' के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए देश के गरीब से गरीब की मौलिक अवश्यकताओं को पूरा करते हुए देश ने एक लंबा रास्ता तय किया है। यह निरंतर अथक मेहनत एवं प्रयासों का ही परिणाम है कि देश में गरीबी में भारी कमी हुई है और पिछले छह वर्षों में 16 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी जो 2011 में 21.2 प्रतिशत थी, 2018 में केवल 6.3 प्रतिशत रह गई है, जो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत एक ऐसा देश है जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगभग सभी मानदंडों पर खरा उतर कर पूरे विश्व को अचम्भे में डाल दिया है।

जन धन, स्वच्छता मिशन, आयुष्मान भारत, पीएम–किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला, उजाला, पीएम–आवास जैसे अनेक अभिनव योजनाओं से समाज के गरीब से गरीब वर्गों का भारी सशक्तिकरण हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि पर बल के साथ–साथ पूरे देश में आधारभूत संरचना का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, उससे सफलता के नए–नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। हर ओर विभिन्न प्रकार के सुधारों की धमक पूरे विश्व में सुनाई पड़ रही है तथा 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के मानदंडों पर चमत्कारी छलांग के साथ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी विकास की कहानी लिख रहा है तथा 'न्यू इंडिया' के लक्ष्यों को प्राप्त करने को तत्पर है। आज जबकि भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का सपना अब सच दिखाई पड़ रहा है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

1250 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ

36 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में 16 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया और दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने तीन ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थलों-वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ने वाली तीसरी कार्पोरेट ट्रेन–महाकाल एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने 430 बिस्तरों वाले सुपर-स्पेशल्टी सरकारी अस्पताल सहित 36 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 14 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केंद्र में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मारक स्थल के साथ स्वयं को जोड़कर आज यह क्षेत्र अपने नाम 'पड़ाव' के महत्व को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर रहा है।

उन्होंने कहा कि यह स्थान ऐसे मंच के रूप में विकसित होगा, जहां सेवा, बलिदान, न्याय और जनहित सब एक स्थान पर होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह स्मारक स्थल और उपवन और यहां स्थापित भव्य प्रतिमा भावी पीढ़ियों को नैतिकता और दीनदयाल जी के विचारों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का मार्ग दिखाया, जो समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विचार से प्रेरणा पाकर 21वीं सदी का भारत अंत्योदय के लिए काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि इस पवित्र अवसर पर लगभग 1250 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जो वाराणसी सहित समूचे पूर्वांचल को लाभान्वित करेंगी। उन्होंने कहा, 'ये सभी परियोजनाएं काशी सहित समूचे पूर्वांचल में पिछले पांच वर्ष से जारी पुनरुद्धार के संकल्प का भाग हैं। इन वर्षों में वाराणसी जिले में 25 हजार करोड़ रुपये मूल्य के विकास कार्यों को पूर्ण किया गया है या वे प्रगति पर हैं।'

ढांचागत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सड़कों, राजमार्गों, जलमार्गों, रेलवे, विशेषकर ढांचागत सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, 'ये विकास कार्य न सिर्फ राष्ट्र को आगे ले जा रहे हैं,

बल्कि रोजगार के अवसरों, विशेषकर पर्यटन आधारित रोजगार के अवसरों का भी सृजन कर रहे हैं, जिनकी काशी और आसपास के क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।' उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति यहां आए थे और वह यहां के दिव्य वातावरण से मंत्रमुग्ध हो गए थे।

उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ के शहर को ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के साथ जोड़ने वाली महाकाल एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बीएचयू में 2016 की दूसरी छमाही में जिस सुपर-स्पेशल्टी अस्पताल का शिलान्यास किया गया था, उसका अब उद्घाटन किया गया है।

उन्होंने कहा, 'मात्र 21 महीनों में यह 430 बिस्तरों वाला अस्पताल काशी और पूर्वांचल की जनता की सेवा करने के लिए तैयार है।' प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी योजनाओं के केंद्र में आत्मनिर्भरता और आत्म-सहायता होने संबंधी दीनदयाल जी के विचारों के अनुरूप, सरकारी योजनाओं और सरकार की संस्कृति में इन विचारों को शामिल करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए उस तक पहुंच बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, "अब परिस्थिति बदल रही है और अब समाज के अंतिम व्यक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।"

'काशी एक रूप अनेक'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी को वाराणसी के बड़ा लालपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यापार सुविधा केंद्र में आयोजित 'काशी एक रूप अनेक' कार्यक्रम में भाग लिया। समारोह के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों और काशी के बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

उन्होंने एक जिला एक उत्पाद के अन्तर्गत हथकरघा, गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौने, चंदौली ब्लैक राइस, कन्नौज के इत्र, मुरादाबाद के धातु शिल्प, आगरा के चमड़े के जूते, लखनऊ की चिकनकारी और आज़मगढ़ की ब्लैक पॉटरी का न केवल निरीक्षण किया, अपितु शिल्पकारों के साथ वार्तालाप भी किया। उन्होंने विभिन्न शिल्पों से जुड़े शिल्पियों और दस्तकारों को किट और वित्तीय सहायता भी प्रदान की।

श्री मोदी ने कहा कि पारंपरिक हस्तशिल्प दस्तकारों, शिल्पियों और एमएसएमई को सुविधा उपलब्ध कराने और मजबूत करने से इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों के लिए अधिक अवसर पैदा करने और कई योजनाओं के तहत बुनकरों और हस्तशिल्पियों को मशीन, ऋण जैसे आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय लेना जारी रखेगी।

एक जिला एक उत्पाद

श्री मोदी ने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों जैसे एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के कारण पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश से निर्यात निरंतर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को उत्तर प्रदेश के उत्पादों से न सिर्फ लाभ होगा, बल्कि यह ऑनलाइन बाजार के माध्यम से दुनिया अन्य हिस्सों तक भी पहुंचेगा।

उन्होंने कहा कि भारत में प्रत्येक जिले की पहचान कुछ अनोखे उत्पादों जैसे रेशम, मसाले आदि की विभिन्न किस्मों से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया और एक जिला एक उत्पाद जैसे विचारों के पीछे ऐसी ही व्यापक प्रेरणा कार्य करती है और यह एक सकारात्मक विकास की ओर ले जाने में सक्षम है।

उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में 30 जिलों के 3500 से अधिक शिल्पी बुनकरों को यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (यूपीआईडी) के द्वारा समर्थित किया गया है। 1000 से अधिक शिल्पियों को टूलकिट भी प्रदान किए गए। उन्होंने बुनकरों, शिल्पियों, हस्तशिल्पियों आदि को

समर्थन देने के लिए यूपीआईडी के प्रयासों की सराहना की।

21वीं सदी की मांग के अनुसार भारत में बने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पारंपरिक उद्योगों को संस्थागत, वित्तीय सहायता के साथ नवीन तकनीक और विपणन जैसी सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों से हम इस दिशा में निरंतर सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि हम एक ऐसे नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। उद्योगों और धन सृजनकर्ताओं की सुविधा के लिए किए गए कई उपायों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में विनिर्माण और व्यापार सुलभता पर काफी जोर दिया गया है।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 1500 करोड़ रुपये का आवंटन

श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 1500 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे के लिए 3700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कॉरिडोर से छोटे उद्योगों को फायदा होगा और इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

उन्होंने उल्लेख किया कि जीईएम (सरकार ई-मार्केटप्लेस) ने छोटे उद्यमों के लिए सरकार को माल बेचना आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि एकीकृत क्रय प्रणाली के निर्माण से सरकार को एक ही मंच पर छोटे उद्योगों से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि देश में पहली बार राष्ट्रीय रसद नीति तैयार की जा रही है, जो एकल खिड़की ई-लॉजिस्टिक्स का निर्माण करेगी, जिससे छोटे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा और रोजगार सृजन में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के समापन पर सभी से भारत को एक विनिर्माण ऊर्जा क्षेत्र बनाने के लिए ठोस प्रयास करने का आग्रह किया।

'श्रीसिद्धान्त शिखामणि ग्रंथ' का 19 भाषाओं में अनुवाद

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी को वाराणसी में जंगमबाड़ी मठ में जगदगुरु विश्वराध्य गुरुकुल के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 'श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ' के 19 भाषाओं में अनुवादित संस्करण का विमोचन भी किया। उन्होंने 'श्रीसिद्धान्त शिखामणि ग्रंथ' मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि यह इत्तेफाक है कि शताब्दी समारोह का आयोजन नए दशक के आरंभ में हो रहा है और यह दशक 21वीं सदी के ज्ञान-विज्ञान में भारत की भूमिका को

विश्व पटल पर फिर प्रतिष्ठापित करने वाला है।

उन्होंने कहा कि मोबाइल ऐप के माध्यम से 'श्रीसिद्धान्त शिखामणि ग्रंथ' का डिजिटलीकरण युवा पीढ़ी के साथ उसके संबंधों को और मजबूत बनाएगा तथा उनके जीवन को प्रेरित भी करेगा। प्रधानमंत्री ने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रंथ से संबंधित विषयों पर वार्षिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन कराने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि 19 भाषाओं में इस ग्रंथ के अनुवाद से इसकी पहुंच व्यापक जनता तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी।

श्री मोदी ने कहा कि नागरिक के रूप में हमारा आचरण भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा, नए भारत की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि संतों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए हमें अपने जीवन के संकल्प पूरे करने हैं और राष्ट्र निर्माण में भी अपना पूरा सहयोग देना है।

प्रधानमंत्री ने स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और स्वच्छता मिशन को देश के कोने-कोने तक ले जाने में जनता के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने जनता से भारत में निर्मित उत्पादों का उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने जल-जीवन मिशन को कामयाब बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से उसमें भाग लेने को कहा।

नमामि गंगे के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी

श्री मोदी ने कहा कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसा केवल जनभागीदारी के कारण संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि 21,000 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में राम मंदिर के निर्माण के लिए 'श्री राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र' ट्रस्ट के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट श्री राम मंदिर के निर्माण की देख-रेख करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने 67 एकड़ जमीन इस ट्रस्ट को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। ■

मध्यप्रदेश, सिक्किम, केरल, महाराष्ट्र एवं मुंबई में नए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नियुक्त

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने मध्य प्रदेश, सिक्किम, केरल, महाराष्ट्र एवं मुंबई भाजपा अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह ने इसकी आधिकारिक घोषणा की।

मध्यप्रदेश

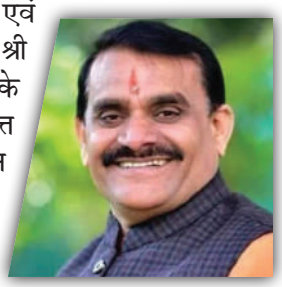

मध्यप्रदेश भाजपा के महासचिव एवं खजुराहो लोकसभा सीट के सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा मध्यप्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष बनाए गए। श्री विष्णु दत्त शर्मा निवर्तमान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री राकेश सिंह की जगह लेंगे। चंबल इलाके के मुरैना से नाता रखने वाले श्री शर्मा ने शुरुआती शिक्षा अपने गांव में ही हासिल की और उसके बाद कृषि में स्नातकोत्तर किया। वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 1986 में जुड़े, जहां वह 2013 तक रहे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री जैसे पदों की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 2013 में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली। पदभार ग्रहण समारोह में श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नेता सब मिलकर पार्टी का नेतृत्व करें और हम सभी कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर हमारे विचारों पर प्रहार करने वाली कमलनाथ सरकार का सामना करें।

सिक्किम

श्री दल बहादुर चौहान को लगातार दूसरी बार भाजपा सिक्किम प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री चौहान का कार्यकाल 2023 तक रहेगा। श्री चौहान ने इस दायित्व के लिए पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद दिया और कहा कि वह राज्य में बूथ-स्तरीय कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी को नयी ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेंगे। प्रदेश इकाई प्रमुख के तौर पर श्री चौहान के पहले कार्यकाल के दौरान भाजपा सिक्किम में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस दौरान एसडीएफ के 10 विधायक भाजपा में शामिल हुए और पार्टी ने विधानसभा के दो उपचुनाव भी जीते।

केरल

श्री के. सुरेंद्रन को पार्टी की केरल इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्थित मराजी भवन में केंद्रीय मंत्री श्री वी. मुरलीधरन और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री एच. राजा समेत सैकड़ों वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद 50 वर्षीय श्री सुरेंद्रन ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा में इस दक्षिणी राज्य में राजनीतिक तौर पर मजबूत होने की ताकत है और कांग्रेस नीत विपक्षी यूडीएफ के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में वह लोगों की आवाज बनेगी। विदित हो कि केरल में इस साल स्थानीय निकाय और 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं।

महाराष्ट्र

श्री चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इससे पहले श्री रावसाहब दानवे पाटिल प्रदेश अध्यक्ष थे। श्री पाटिल पुणे शहर में कोथरूड विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे पिछली साल भाजपा-शिवसेना सरकार में राजस्व एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने पुणे और कोल्हापुर के पालकमंत्री का भी दायित्व संभाला है।

मुंबई

श्री मंगल प्रभात लोढ़ा को भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। उन्हें लगातार दूसरी बार अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री लोढ़ा मुंबई के मलबार हिल विधानसभा सीट से सन 1995 से लगातार छठी बार विधायक हैं। विधानसभा चुनावों से पहले 16 जुलाई 2019 को श्री मंगल प्रभात लोढ़ा को मुंबई भाजपा का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्होंने मुंबई में पार्टी को 17 सीट में से 16 विधायक जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1955 में जोधपुर में जन्मे श्री मंगल प्रभात लोढ़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे। ■

भारतीय जनता पार्टी 'विकास' की पर्यायवाची बन गई है: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 22 फरवरी को बिहार प्रदेश भाजपा मुख्यालय, पटना में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बिहार के 11 जिले अरवल, नवगछिया, भागलपुर, सहरसा, शिवहर, लखीसराय, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीवान, औरंगाबाद और सासाराम के नवनिर्मित भाजपा कार्यालयों का उद्घाटन किया और इस अवसर पर प्रदेश भाजपा कार्यालय में भारी संख्या में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेणु देवी, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेन्द्र यादव, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री सौदान सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्य सभा संसद श्री सीपी ठाकुर, बिहार विधानसभा में भाजपा विधायक दल के नेता श्री प्रेम कुमार, बिहार सरकार में मंत्री श्री नंदकिशोर यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राधामोहन सिंह और सांसद श्री आर. के. सिन्हा के साथ कई भाजपा सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने कहा कि श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण के छात्र आंदोलन ने मुझे राजनीतिक दृष्टि दी और अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। उन्होंने कहा कि बिहार प्रदेश कार्यालय से मेरा विशेष संबंध रहा है। मैं यहां की मिट्टी में पला-बढ़ा हूं। आज मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज यहीं से मुझे प्रदेश के 11 नवनिर्मित कार्यालयों के उद्घाटन का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए पांच 'क' अर्थात् कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यकारिणी, कोष और इन सब गतिविधियों को संचालित करने के लिए कार्यालय की जरूरत होती है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की कल्पना की और इसे साकार करने की पहल की। आज मुझे यह कहते हुए गर्व और ख़ुशी का अनुभव हो रहा है कि देश के 590 जिलों में कार्यालय के लिए जमीन के खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है जिसमें 487 जिलों में भाजपा कार्यालयों का निर्माण हो चुका है। बाकी जिलों में जमीन खरीद की प्रक्रिया जारी है। इसी तरह बिहार प्रदेश में भी 45 जिलों में से 36 जिले में जमीन खरीद की प्रक्रिया पूरी हो गई है जिसमें से 11 जिलों में पार्टी कार्यालय का निर्माण हो चुका है जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। अगले दो महीने में छः और जिलों में कार्यालयों का निर्माण हो जाएगा और इस वर्ष के अंत तक 13 और भाजपा जिला कार्यालयों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कार्यालय केवल एक ढांचा नहीं है, बल्कि काम करने का मंदिर है। ये कार्यालय मॉडर्न फैसिलिटी से सुसज्जित हैं जहां लाइव

वीडियो-ऑडियो कांफ्रेंसिंग, ई-लाइब्रेरी, कांफ्रेंस रूम, मीटिंग रूम और रिसेप्शन की सुविधा है। मैं बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि ये जिला कार्यालय भाजपा की जड़ों को और मजबूत करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे।

श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, संगठन और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम की बुनियाद पर खड़ी पार्टी है जिसके लिए हमेशा 'नेशन फर्स्ट' होता है। देश में मौजूद बाकी सभी राजनीतिक दलों के लिए परिवार ही पार्टी है जबकि हमारे लिए पार्टी ही परिवार है। बाकी पार्टियां वंशवाद, जातिवाद और परिवारवाद के आधार पर चलती हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, संगठन और विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ती है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस, राजद और इनकी सहयोगी पार्टियों के लिए उनका वोट बैंक और परिवार पहले आता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश सबसे पहले आता है। श्री नड्डा ने कहा कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए विकास की नित-नई कहानियां लिख रहा है। भाजपा-जदयू-लोजपा ने बिहार की विकासवादी छवि सृजित की है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का बिहार से विशेष लगाव है, इसलिए उन्होंने बिहार के विकास पर विशेष ध्यान दिया है।

श्री नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पुनः एनडीए की सरकार का गठन हो, इसके लिए हमें पूरा जोर लगाना है। श्री नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 'विकास' की पर्यायवाची बन गई है। विकास का दूसरा नाम भाजपा है। सबको साथ लेकर चलना, सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और देश को हमेशा आगे रख कर काम करना भारतीय जनता पार्टी की नीति है। ■

'हमने विकासवाद को राजनीति का आधार बनाया और सत्ता को सेवा का माध्यम'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 16 फरवरी को नवी मुंबई में महाराष्ट्र राज्य भाजपा परिषद् अधिवेशन को संबोधित किया और पार्टी पदाधिकारियों, राज्य के भाजपा जन-प्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। अधिवेशन में 10,000 से अधिक पार्टी पदाधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिसमें राज्य के भाजपा सांसद, विधायक, मेयर, महापौर और नगर सेवक के साथ-साथ महाराष्ट्र में पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष एवं सभी मोर्चों के अध्यक्ष भी शामिल हैं। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने के बाद श्री नड्डा का यह पहला महाराष्ट्र दौरा था।

श्री नड्डा ने कहा कि यह विचारधारा हमारे मनीषी नेताओं की नेतृत्व क्षमता, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा और सत्ता को जन-सेवा का माध्यम बनाने की हमारी नीति का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 17 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज देश में भाजपा के 385 सांसद, लगभग 1325 विधायक और काफी बड़ी संख्या में पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि जन संघ से लेकर अब तक के हमारे सभी प्रस्तावों में एकरूपता है, निरंतरता है। भाजपा आज तक अपने विचारों से डिगी नहीं, लगातार अपने ध्येय को लेकर चलती रही।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विगत छः वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जो कार्य किये हैं और जो निर्णय लिए हैं, वे अकल्पनीय हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और गृह मंत्री श्री अमित शाह की रणनीति के बल पर धारा 370 धाराशायी हुआ और जम्मू-कश्मीर में विकास का नया सबेरा हुआ। धारा 370 और 35A के खात्मे से घाटी में आतंकवाद, अलगाववाद और भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार हुआ और शांति कायम हुई। आजादी के बाद पहली बार जम्मू-कश्मीर में बीडीसी के चुनाव हुए और 80 सीटों पर विजय के साथ भाजपा को आशातीत सफलता मिली, जबकि कांग्रेस महज एक सीट जीत पाई। पीडीपी-एनसी तो चुनाव मैदान छोड़ भाग खड़े हुए।

श्री नड्डा ने कहा कि 500 वर्षों से चले आ रहे अयोध्या विवाद का हल हुआ और उस जगह पर भगवान् श्रीराम का भव्य मंदिर बनने का रास्ता प्रशस्त हुआ जहां प्रभु श्रीराम का जन्म हुआ था। हमने सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इसी कड़ी में हमने ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को ख़त्म कर मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। पहली बार यूएपीए और एनआईए जैसे कानून लागू हुए और काले धन को रोकने का सार्थक प्रयास किया गया।

श्री नड्डा ने कहा कि सीएए को लेकर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों ने अराजकता फैलाने की कोशिश की, जनता को गुमराह कर दंगे कराने की साजिश रची जबकि हमने बार-बार विरोध कर रहे लोगों से पूछा कि सीएए के किस प्रावधान को लेकर आपको दिक्कत है लेकिन वे बताते नहीं। वे बता पायेंगें भी नहीं क्योंकि सीएए का हिंदुस्तान के नागरिकों से कोई लेना-देना ही नहीं है। वास्तविकता यह है कि देश में विपक्ष के लिए वोट बैंक पहले आता है जबकि हमारे लिए देश सबसे पहले आता है। हम केवल और केवल देश के बारे में सोचते हैं, इसलिए हर वह कदम उठाते हैं जो देश के लिए उचित है।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में आज हमारी सरकार नहीं है लेकिन पांच वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की देवेन्द्र फड़णवीस सरकार ने राज्य के विकास के लिए इतने काम किये कि आज भी जनता हमारी सरकार को याद कर रही है लेकिन आज महाराष्ट्र की तीन पहिये वाली सरकार देवेन्द्र फड़णवीस सरकार द्वारा शुरू किये गए विकास कार्यों में रुकावट उत्पन्न कर रही है। इन्फ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपये महाराष्ट्र में देवेन्द्र फड़णवीस सरकार ने खर्च किये। शिक्षा के क्षेत्र में पांच साल पहले महाराष्ट्र 17वें और स्वास्थ्य में छठे स्थान पर था, जबकि देवेन्द्र फड़णवीस सरकार के पांच सालों के कार्यकाल में ही महाराष्ट्र इन दोनों क्षेत्र में तीसरे स्थान पर आ गया। जलयुक्त शिवार अभियान ने समग्र भारत में जल संचयन और जल संरक्षण की दिशा में एक नई मिसाल कायम की। स्वच्छ भारत अभियान में भी देवेन्द्र फड़णवीस सरकार के समय महाराष्ट्र ने सफल योगदान दिया।

श्री नड्डा ने कहा कि हमने महाराष्ट्र में देवेन्द्र फड़णवीस के नेतृत्व में भाजपा की स्थिर और स्थायी सरकार दी। हमने विकासवाद को राजनीति का आधार बनाया, सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया और प्रदेश की छवि और तसवीर को बदलने का कार्य किया। ■

भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था: आईएमएफ

क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के संदर्भ में भारत की जीडीपी (पीपीपी) 10.51 ट्रिलियन डॉलर है

श्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जब साल 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने देश का शासन संभाला था, तब विश्व अर्थव्यवस्था में भारत 9वें स्थान पर था। अक्टूबर में आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत अब फ्रांस, ब्रिटेन से आगे निकल गया और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।

देश की जीडीपी वृद्धि दर पिछले एक दशक में दुनिया में सबसे अधिक रही है- जो नियमित रूप से 6-7% की वार्षिक दर से बढ़ी है।

मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की साल 2016 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार इस तेजी के लिए कई कारक जिम्मेदार है, जिसमें मुख्य रूप से शहरीकरण और प्रौद्योगिकियों क्षेत्र में सुधार शामिल है।

साल 2010 तक भारत, ब्राजील और इटली जैसे देशों से पीछे था और 9वें स्थान पर बना हुआ था।

पिछले 25 वर्षों में भारत का उदय एक नाटकीय अंदाज में हुआ है और साल 1995 के बाद भारत की में 700% से अधिक की वृद्धि देखी गई है।

यह प्रगति उल्लेखनीय है। अत्यधिक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में, साल 2000 से साल 2015 तक 160 मिलियन की कमी आयी है।

विश्व बैंक के अनुसार, देश ने सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर अपनी नीतियों को समायोजित किया है और भारत भविष्य में अपने विकास की संभावानाओं को अधिक मजबूत और समावेशी बनाने के उपाय कर रहा है।

अमेरिका-आधारित थिंक टैंक वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2.94 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था गया है, साल 2019 में ब्रिटेन और फ्रांस को पछाड़कर भारत ने इस मुकाम को हासिल किया है। गौरतलब है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार 2.83 ट्रिलियन डॉलर है और फ्रांस की अर्थव्यवस्था का आकार 2.71 ट्रिलियन डॉलर है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि क्रय शक्ति समानता (पीपीपी) के संदर्भ में भारत की जीडीपी (पीपीपी) 10.51 ट्रिलियन डॉलर है, जो जापान और जर्मनी से अधिक है। भारत की अधिक जनसंख्या के कारण भारत का जीडीपी प्रति व्यक्ति आय 2,170 डॉलर (यूएस का 62,794 डॉलर) है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण 1990 के शुरुआती दौर में आरंभ हुआ। इसमें औद्योगिक नियंत्रण, विदेशी व्यापार और निवेश पर नियंत्रण और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण शामिल था।

"इन उपायों ने भारत को अपने आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद की है।"

भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का 60 प्रतिशत है और 28 प्रतिशत रोजगार देने वाले के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के दो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ■

ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं
जीडीपी, वर्तमान मूल्य- अमेरिकी डॉलर

	2010	2019
1.	अमेरिका	अमेरिका
2.	चीन	चीन
3.	जापान	जापान
4.	जर्मनी	जर्मनी
5.	फ्रांस	भारत
6.	ब्रिटेन	ब्रिटेन
7.	ब्राजील	फ्रांस
8.	इटली	इटली
9.	भारत	ब्राजील
10.	रूस	कॅनाडा

स्रोत: आईएमएफ

2019-20 के लिए 291.95 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के आसार

केंद्रीय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 18 फरवरी को 2019-20 के लिए खाद्यान्न, तिलहन और अन्य वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया। मॉनसून (जून से सितंबर, 2019) के दौरान देश में संचयी वर्षा दीर्घकालिक औसत (एलपीए) की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक हुई। इसके मद्देनजर कृषि वर्ष 2019-20 के लिए अधिकतर फसलों के उत्पादन का अनुमान सामान्य उत्पादन की अपेक्षाकृत अधिक आंका गया है। समय-समय पर मिलने वाली सटीक सूचनाओं के आधार पर इन आंकलनों में सुधार किया जा सकता है।

दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2019-20 के दौरान प्रमुख फसलों का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:

खाद्यान्न – 291.95 मिलियन टन (रिकॉर्ड)	
चावल – 117-47 मिलियन टन (रिकॉर्ड)	सोयाबीन – 13.63 मिलियन टन
गेहूं – 106.21 मिलियन टन (रिकॉर्ड)	रेपसिड और सरसों – 9.11 मिलियन टन
पोषक/मोटा अनाज – 45.24 मिलियन टन	मूंगफली – 8.24 मिलियन टन
ज्वार – 28.08 मिलियन टन	कपास – 34.89 मिलियन गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम)
दालें – 23.02 मिलियन टन	जूट और मेस्टा – 9.81 मिलियन गांठ (प्रत्येक 180 किलोग्राम)
तूर – 3.69 मिलियन टन	गन्ना – 353.85 मिलियन टन
चना – 11.22 मिलियन टन	तिलहन – 34.19 मिलियन टन

वर्ष 2019-20 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 291.95 मिलियन टन होने की आशा है, जो 2018-19 के 285.51 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन से 6.74 मिलियन टन अधिक है। लेकिन 2019-20 के दौरान उत्पादन पिछले पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 26.20 मिलियन टन से अधिक है।

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल चावल उत्पादन 117.47 मिलियन टन होने का अनुमान है। यह पिछले पांच वर्षो के 107.80 मिलियन

टन के औसत उत्पादन की तुलना में 9.67 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान गेंहू का रिकॉर्ड 106.21 मिलियन टन उत्पादन होगा। यह 2018-19 के गेंहू उत्पादन की तुलना में 2.61 मिलियन टन अधिक है और 94.61 मिलियन टन के औसत गेंहू उत्पादन से 11.60 मिलियन टन अधिक है।

पौष्टिक मोटे अनाजों का उत्पादन 45.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जोकि 2018-19 के 43.06 मिलियन टन उत्पादन से 2.18 मिलियन टन अधिक है। यह औसत उत्पादन से भी 2.16 मिलियन टन ज्यादा है। वर्ष 2019-20 में दालों का कुल उत्पादन 23.02 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों के 20.26 मिलियन टन के औसत उत्पादन से 2.76 मिलियन टन अधिक है।

देश में वर्ष 2019-20 के दौरान तिलहन का कुल उत्पादन 34.19 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2018-19 के 31.52 मिलियन टन उत्पादन से 2.67 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2019-20 के दौरान तिलहनों का उत्पादन औसत तिलहन उत्पादन से 4.54 मिलियन टन अधिक है।

देश में वर्ष 2019-20 के दौरान कुल गन्ना उत्पादन 353.85 मिलियन टन होने की आशा है। 2019-20 के दौरान गन्ना उत्पादन 349.78 मिलियन टन के औसत गन्ना उत्पादन से 4.07 मिलियन टन अधिक है। कपास का उत्पादन 34.89 मिलियन गांठ (प्रत्येक 170 किलोग्राम की) होने का अनुमान है, जो 2018-19 के 28.04 मिलियन गांठ से 6.85 मिलियन गांठ अधिक है। जूट और मेस्ता का उत्पादन 9.81 मिलियन गांठ (प्रत्येक 180 किलोग्राम की) होने का अनुमान है। ■

'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना के पांच वर्ष पूरे

वर्ष 2015-17 के दौरान 10.74 करोड़ और 2017-19 के दौरान 11.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित

19 फरवरी 2020 को महत्वपूर्ण 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड' योजना के पांच वर्ष पूरे हो गए। इसी दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत वर्ष 2015-17 (चक्र-1) के दौरान 10.74 करोड़ और वर्ष 2017-19 (चक्र-2) के दौरान 11.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए गए। पांच साल पहले इसे शुरू करने के बाद से सरकार इस योजना पर 700 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर चुकी है।

इस योजना के तहत 2014-15 से लेकर अब तक 429 नई स्टैटिक सॉयल टेस्टिंग लैब्स (एसटीएल), 102 नई मोबाइल एसटीएल, 8752 मिनी एसटीएल और 1562 ग्राम स्तरीय एसटीएल मंजूर की जा चुकी है। इन स्वीकृत प्रयोगशालाओं में से 129 नई स्टैटिक सॉयल टेस्टिंग लैब्स (एसटीएल), 86 नई मोबाइल एसटीएल, 6498 मिनी एसटीएल और 179 ग्राम स्तरीय एसटीएल अब तक स्थापित की जा चुकी हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य हर दो साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि खाद डालने के तरीकों में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए एक बुनियाद प्रदान की जा सके। पोषक तत्व प्रबंधन के आधार पर मिट्टी के परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए ही मृदा परीक्षण को विकसित किया गया है। उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग करवाकर मृदा परीक्षण खेती की लागत को कम करता है। यह पैदावार में वृद्धि करके किसानों की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करता है और टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा देता है।

देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। ये कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक भी सुझाता है। गौरतलब है कि मिट्टी के रासायनिक, भौतिक और जैविक स्वास्थ्य की गिरावट को भारत में कृषि उत्पादकता में ठहराव के कारणों में से एक माना जाता है।

सरकार पोषण आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना को भी लागू कर रही है और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए अनुकूलित और मज़बूत बनाए हुए उर्वरकों को बढ़ावा दे रही है। अब तक 21 उर्वरकों को एनबीएस योजना के तहत लाया जा चुका है। वर्तमान में सरकार द्वारा अधिसूचित 35 अनुकूलित और 25 मज़बूत बनाए हुए उर्वरक उपयोग में हैं।

2019-20 के दौरान 'मॉडल ग्रामों का विकास' नाम की पायलट परियोजना शुरू की गई, जहां मिट्टी के नमूनों का संग्रह ग्रिड में करने के बजाय किसान की भागीदारी के साथ उसके खेत में किया जाता है। इस पायलट परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक से एक गांव को गोद लिया जाता है ताकि मृदा परीक्षण किया जा सके और बड़ी संख्या में प्रदर्शनों का आयोजन किया जा सके, जिसमें प्रदर्शनों की अधिकतम सीमा 50 प्रति हेक्टेयर है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य हर दो साल में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि खाद डालने के तरीकों में पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए एक बुनियाद प्रदान की जा सके। पोषक तत्व प्रबंधन के आधार पर मिट्टी के परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए ही मृदा परीक्षण को विकसित किया गया है।

राज्यों के द्वारा अब तक 6,954 गांवों की पहचान की जा चुकी है, जहां 26.83 लाख नमूनों/मृदा स्वास्थ्य कार्डों के लक्ष्य के मुकाबले 21.00 लाख नमूने एकत्र किए जा चुके हैं। 14.75 लाख नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है और 13.59 लाख कार्ड किसानों में वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, राज्यों द्वारा 2,46,979 प्रदर्शनों और 6,951 किसान मेलों को मंजूरी प्रदान की गई है।

अगले पांच वर्षों में चार लाख गांवों को व्यक्तिगत रूप से खेती करने के लिए मिट्टी का नमूनाकरण करने और परीक्षण करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। 2.5 लाख प्रदर्शनों का आयोजन, गांव के स्तर पर 250 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, 200 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को युग्मित प्लाज्मा (आईसीपी) के साथ मजबूती प्रदान करना और 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों को बढ़ावा देना शामिल किया गया है।

2017 में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (एनपीसी) के द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि एसएचसी योजना के माध्यम से टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया गया है और इसके द्वारा 8-10 फीसदी तक रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में कमी आई है। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उपलब्ध सिफारिशों के अनुसार, उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग करने के कारण फसलों की उपज में 5-6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। ■

आत्मिक सुख की आवश्यकता

दीनदयाल उपाध्याय

अंतिम भाग

एक बार लखनऊ के अस्पताल में एक लड़का आया था, उसे बहुत पहले भेड़िए उठाकर ले गए थे। भेड़ियों ने ही उसका लालन-पालन किया। इसका फल यह हुआ कि मनुष्य समाज से वह बिल्कुल दूर हो गया। वह भेड़िए की तरह ही बोलता था। खाना भी वह हाथ से नहीं खाता था। ज़बान से लप-लप करके खाना खाता था। जैसे चौपाए चलते हैं, वैसे ही वह चलता था। अब उसमें धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन हुए हैं। उसको मनुष्यों में लाकर रखा गया है। उस लड़के का जैसा हाल हुआ, समाज से हटकर हम सभी का वही हाल हो सकता है। समाज के कारण ही हम बोलना, चलना, हंसना सीखते हैं। हमारी बुद्धि का विकास भी समाज के द्वारा ही होता है। यदि समाज न हो तो हम कुछ भी नहीं सीख सकते। हम पिछले ज्ञान से सीखकर नए ज्ञान की ओर बढ़ते हैं।

जैसे प्रारंभ में मनुष्य ने आग का आविष्कार किया होगा। आग जलाना सीखा होगा। उसके लिए न मालूम कितनी बुद्धि लगाई होगी। कितने प्रयत्न किए होंगे। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद उसने आग जलाना सीख ही लिया। लेकिन क्या हमें आज इतनी बुद्धि लगानी पड़ती है? नहीं, इसी तरह गुणा, भाग, जोड़, घटा आदि का ज्ञान है। हम हिसाब लगा लेते हैं। लेकिन यह सब आविष्कार किसने किया? शून्य की खोज, जिस प्रकार हम संख्याएं लिखते हैं-इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यह सब आविष्कार कैसे हुआ? कितने ही लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई होगी। यूरोप के लोग जिसका आविष्कार नहीं कर पाए, रोमन न्यूमरल्स यों लिखे जाते हैं। यह आपने देखा होगा। जैसे अंग्रेज़ी का 'वी' होता है, उसे पांच कहा जाता है। जबकि हम लोग पंद्रह लिखते हैं तो एक और पांच इस तरह लिखते हैं। यह सब जो चीज़ है, इसके लिए हमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती। लेकिन हमारे लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। इसलिए हम समाज से हटकर यदि जीना चाहें तो नहीं जी पाएंगे।

हम जो कर रहे हैं, उसका फल आगे आनेवाले समय में किसी और को मिलेगा तथा जो हमसे पहले कर गए हैं, उनकी मेहनत का फल हमें प्राप्त हुआ, जो एक धरोहर के रूप में प्राप्त होता चला जाता है। हमारी यात्रा इसी तरह चलती रहती है। यानी हम सब किसी-न-किसी रूप में एक-दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। व्यक्ति का समाज से घनिष्ठ संबंध है। यदि समाज सुखी नहीं होगा तो व्यक्ति भी सुखी नहीं रह सकता। समाज हमें बहुत कुछ देता है, जिससे व्यक्ति अनजान रहता है। समाज सब चीजें देकर भी ऐसा कुछ नहीं दिखा पाता, जैसे कोई रुक्का लिखा दे। क़र्ज़ा देते समय रुक्का लिखा देते हैं। यानी रुपया दिया तो लिखा लिया कि सौ रुपया दिया, इसके ऊपर पांच रुपए का ब्याज़ लगेगा। इस हिसाब से तुम मुझे वापस कर दोगे। किंतु समाज तो हमसे ऐसा कुछ लिखवाता ही नहीं है। हमें सबकुछ देता चला जाता है। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से सोचे तो उसे लगेगा कि वह वास्तव में समाज का क़र्ज़दार है।

कितनी अच्छी-अच्छी चीजें, अच्छे-अच्छे गुण हैं-ये सब हमें समाज से ही तो प्राप्त होते हैं। हमें समाज का क़र्ज़ चुकाना है, इस तरह का विचार करना चाहिए। हमारी भलाई समाज के साथ ही जुड़ी हुई है। अब यदि भला नहीं होगा तो समाज को उतना ही दुःख होगा। समाज की अवस्था गिरती चली जाएगी। इस प्रकार समाज का कार्य यदि करना है तो समाज के सुख के साथ अपने सुख का विचार करना है। इन दोनों का आपस में बड़ा संबंध है। इस संबंध को हमें अच्छी प्रकार समझना है। परंतु इस संबंध में एक बात ज़रूर है कि आपने समाज का ही विचार किया और व्यक्तिगत विचार बिल्कुल ही नहीं किया तो भी कठिनाई होगी, क्योंकि समाज एक ऐसी स्वाभिव्यक्ति की चीज़ है कि वह जो भी काम करता है, व्यक्तियों द्वारा ही करता है। अकेला समाज भी कुछ नहीं कर सकता।

समाज क्या है? समाज तो दिखाई नहीं देता। यह अमूर्त रूप में है। यह क्रियाशील होता है तो वास्तव में मनुष्यों द्वारा ही क्रियाशील होता है। यद्यपि समाज के सुख में ही व्यक्ति का सुख है, परंतु समाज व्यक्तियों द्वारा ही काम करेगा। जैसे घड़ी है। घड़ी की सुई की जो कुछ सार्थकता है, वह इसी बात में है कि घड़ी ठीक प्रकार से चले। किंतु क्या घड़ी का हम विचार कर सकते हैं, जिसमें सुई न हो, ऐसी कोई घड़ी जिसकी सुई ठीक न हो। वह घड़ी किस काम की। अगर कोई सोचे कि इसमें सुई की क्या क़ीमत है? केवल घड़ी की क़ीमत है, सुई की कोई क़ीमत नहीं तो ऐसा नहीं है। घड़ी के हर एक पर्जे की कीमत है। स्प्रिंग है। यदि हम समझें कि उसकी कोई कीमत नहीं है। उसे फेंक दो तो घड़ी काम नहीं करेगी। घड़ी का डायल भी ठीक होना चाहिए। सभी पुर्जे ठीक हों और घड़ी के साथ ठीक होने चाहिए। अलग-अलग किसी चीज़ की क़ीमत नहीं। मोटर के बारे में भी यही बात है कि मोटर की अलग-अलग चीज़ों की कोई क़ीमत नहीं। मोटर की हर चीज़ अलग होने से निरर्थक हो जाएगी। लेकिन जब तक उन्हें जोड़ा न जाए, जब तक मोटर ठीक नहीं चलेगी। वह तभी चलेगी जब उसके सभी पुर्जे ठीक होने के साथ-साथ मोटर से जोड़े जाएं। प्रत्येक वस्तु में परस्पर पूरकता का संबंध रहता है। व्यक्ति और समाज का भी ठीक वैसा ही संबंध है।

दोनों का विचार कर चलना चाहिए, अन्यथा सब कुछ अधूरा रह जाएगा। पूर्ण रूप से विकसित न हुआ तो काम नहीं चलेगा। यदि कोई केवल मोटर का ही विचार करे और उसके पुर्जे का विचार न करें तो भी वह अधूरी ही रहेगी और काम नहीं कर सकेगी। जब व्यक्ति और समाज दोनों को सुख प्राप्त होगा, तभी सब कुछ पूर्णता को प्राप्त हो सकेगा। कुछ लोग केवल व्यक्ति का ही विचार करते हैं, समाज का नहीं करते। कुछ समाज का ही विचार करते हैं, व्यक्ति का नहीं करते। हमें एक ही पक्ष का विचार नहीं करना चाहिए? हमें दोनों पक्षों का विचार कर चलना चाहिए। जो लोग सिर्फ़ व्यक्ति का ही विचार करते हैं, वे यह नहीं सोचते कि मनुष्य की स्वतंत्रता क्यों है, किसके लिए है? व्यक्ति का संबंध किसके लिए है। वे यह नहीं सोचते कि जीवन में कौन सी दिशा होनी चाहिए। इस प्रकार से दो बातों का एक प्रकार से एक्सट्रीम विचार लेकर चलने वाले हज़ारों लोग सृष्टि में दिखाई देते हैं। किंतु हमारे यहां पर जो कुछ विचार हुआ वह यह कि व्यक्ति को समाज से अलग नहीं किया जा सकता और न ही बिना व्यक्तियों के समाज जैसी कोई चीज़ है। दोनों का हमें सामूहिक रूप से विचार करना पड़ता है। दोनों का विकास कैसे हो, इसकी चिंता लेकर हम चलते हैं।

इसी तरह व्यक्ति के अंदर भी हमने विचार किया कि व्यक्ति का जीवन केवल भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से है, हमें उसका ही विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसकी मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की उन्नति का भी विचार करके चलना पड़ता है। इस प्रकार हमें सामूहिक विचार करना पड़ता है। यह पूर्णता जहां होगी, वहां ही हमारा वैभव हो सकता है। जहां यह पूर्णता नहीं, जहां हमारा समाज दुनिया में बदनाम हो गया है, हमारा समाज गुलाम हो गया है, वहां हमें वैभव प्राप्त नहीं हो सकता।

जैसे स्वामी विवेकानंदजी सारी दुनिया में घूम आए और दुनिया में बड़ा नाम कमाया। लोगों ने कहा कि देखा, इतना बड़ा, इतना ऊंचा विद्वान इनके पास है। लेकिन इतना होते हुए भी समाज के प्रतिनिधि के नाते से वे गए। भारत के प्रति लोगों की बड़ी नीची दृष्टि रही। भारत कई सौ वर्षों तक गुलाम था। यदि समाज का बड़ा नाम हो जाए और समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, उन्हें किसी प्रकार का सुख प्राप्त न हो, तो वह बड़ा नाम छोटा हो जाएगा। उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वह केवल दिखावे की चीज़ हो जाएगी ऊपर से। वास्तविकता उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगी। अगर हम उसमें

व्यक्ति का जीवन केवल भौतिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से है, हमें उसका ही विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसकी मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की उन्नति का भी विचार करके चलना पड़ता है। इस प्रकार हमें सामूहिक विचार करना पड़ता है। यह पूर्णता जहां होगी, वहां ही हमारा वैभव हो सकता है।

वास्तविकता चाहते हैं तो वह तभी रहेगी जब व्यक्ति और समाज का जो अभिन्नता का संबंध है, उसके आधार पर ही दोनों का विकास हो सके।

जब हम इस नाते से विचार करते हैं तो व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक जीवन और इसी प्रकार से व्यक्ति और समष्टि को सुखी बनाने तथा उनका विकास करने की दृष्टि से। तब हम व्यक्तियों के समूह और अनेक प्रकार की संस्थाओं को निर्मित करते हैं। राज्य भी इनमें से ही एक संस्था है। हमारे यहां पर तो और भी संस्थाएं निर्माण हुई हैं, जैसे हमारे यहां कुटुंब की पद्धति है, पश्चिम में कुटुंब जैसी कोई चीज़ नहीं है। अपने यहां तो विवाह होने के बाद पिता-पुत्र साथ-साथ रहते हैं, लेकिन पश्चिम में विवाह हुआ कि पुत्र और पुत्रवधू अलग हो जाते हैं। फिर उनका पिता के साथ कोई संबंध नहीं रहता। अपने यहां यह चीज़ नहीं है। कुटुंब की पद्धति है, जाति की पद्धति है, वर्णों की पुरानी पद्धति है। अपने यहां पंचायत की पद्धति है और अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं और समाज वास्तव में साधर्म्य का निर्वाह करने के लिए तथा समन्वय को प्रतिस्थापित करने के लिए निर्मित होती रहती हैं। अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समाज इस प्रकार की अनेक संस्थाओं का निर्माण करता है।

पश्चिम में भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं। पारस्परिक संबंध की दृष्टि से जितना विचार किया जाना चाहिए था। शायद उसमें उतना नहीं किया जाता। जैसे राज्य की संस्था है। यह राज्य की संस्था सारी दुनिया में है। आज भी है, पहले भी थी। पश्चिम ने भी राज्य संस्था निर्माण की है। बाक़ी भी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे उपासना पद्धति की दृष्टि से विभिन्न उपासना पद्धति को मानने वाले संप्रदाय के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह भी उनकी एक संस्था है। जैसे ईसाइयों में चर्च में भी अनेक चर्च हैं। कोई प्रोटेस्टेंट चर्च है, कोई जेसुइस्ट है और बाक़ी के मेथोडिस्ट हैं और अनेक छोटे-छोटे भेद हैं। उन भेदों को लेकर भी सेक्टर्स निर्माण हो गए हैं। इस प्रकार की उपासना पद्धति को मानने वाले कुछ लोग हैं। एक प्रकार की राजनीतिक विचारधारा को लेकर चलने वाले कुछ लोग हैं, इस प्रकार के राजनीतिक स्वार्थों को लेकर पूर्ण करने का प्रयत्न करने वाले कुछ लोग हैं। राजनीतिक पार्टी के रूप में उनका निर्माण हो जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी कहीं पर मज़दूरों का संगठन खड़ा है, कहीं पर रुपया लगाने वाले पूंजीपतियों ने भी अपने संगठन बना रखे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटियां चलती हैं। साहित्यिकों के क्लब निर्माण होते हैं। इस प्रकार के अनेक संगठन पश्चिम में भी निर्माण हुए हैं। आज भी हो रहे हैं, किंतु आज भी उनकी समझ में यह नहीं आया कि इन सब संगठनों का पारस्परिक संबंध क्या

होना चाहिए?

ये संगठन वास्तव में किस एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए गए हैं, इन संगठनों का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस बात का शायद वे ठीक प्रकार से अनुमान नहीं लगा पाए हैं। हमारे यहां भी पहले इस प्रकार के अनेक संगठन चले थे। आज भी उनके कुछ अवशेष विद्यमान हैं। उनमें से आज बहुत कुछ ध्वंस हो गए होंगे। कुटुंब का संगठन है, जाति का संगठन है, वर्ग का संगठन है, उपासना पद्धति के नाते संगठन है। अपने यहां पर चले। ये सभी प्रकार के संगठन हैं। बाक़ी की भी बहुत चीजें रहीं। वास्तव में अनेक रूप हैं। समाज सभी संगठनों द्वारा अपना कार्य पूरा करता है। व्यक्ति भी इन संगठनों के द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। प्रत्येक देश में इस तरह की अपनी-अपनी पद्धति होती है।

हमारे देश के संगठनों में परस्पर समन्वय था, सामंजस्य था। सभी लोग सामंजस्य के ऊपर ठीक-ठीक प्रकार से चलते थे। वे समाज के लिए पूरक बनकर चलते थे। यदि वे आज नहीं चलते हैं तो इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि उनके पीछे का सामंजस्य समाप्त हो गया है। किंतु इसके पीछे एक तर्क है जिसे गंभीरता से सोचेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा कि यह जो अपने जीवन की पूर्णता की कल्पना है, उन कल्पनाओं का आधार लेकर है। हमने इतने प्रकार के भिन्न-भिन्न साधन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही निर्माण किए हैं और प्रत्येक संगठन के पीछे यह जो पूर्णता की कल्पना है, यह पूर्णता कल्पना में निहित है। यह प्रत्येक प्रकार के संगठनों के पीछे हमारी जो जीवन की मूल कल्पना है, उनका सबका विवेचन यहां पर करना नहीं, सिर्फ इतना मानकर चलते हैं कि हमारे यहां पर भी अनेक प्रकार के ऐसे संगठन हैं, जिनकी स्थिति अब जीवंत नहीं है, बल्कि वे एक प्रकार से निष्प्राण होकर चल रहे हैं। फिर सजीव हों या न हों, उसके संबंध में अनेक मत हो सकते हैं। किंतु यह बात सत्य है कि अपने यहां मूल भावना पर विचार करके व्यक्ति और समाज में क्या संबंध है, इसका विचार करके चलें और उसके साथ ही इस दृष्टि से चलाने का विचार करें। ■

समाप्त

-पाञ्चजन्य, मई 27, 1961, संघ शिक्षा वर्ग, बौद्धिक वर्ग : लखनऊ

पं दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि (11 फरवरी) पर कार्यक्रम

'एकात्म मानववाद का दर्शन न केवल भारत अपितु सम्पूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 11 फरवरी को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में देश को अंत्योदय व एकात्म मानववाद की दृष्टि देने वाले, जनसंघ के संस्थापक एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा मुख्यालय में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री बी एल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख श्री संजय मयूख, कार्यालय सचिव श्री महेंद्र पांडेय सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों व सिद्धांतों के बीज ने देश को एक वैकल्पिक विचारधारा दी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एवं अंत्योदय के सिद्धांत पर एक नए भारत की कल्पना की थी। उनका पूरा जीवन जन-कल्याण, राष्ट्र के उत्थान और संस्कृति के संरक्षण के प्रति समर्पित रहा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सबसे पहले देश, उसके बाद पार्टी और अंत में मैं के सिद्धांत की राजनीति से कार्यकर्ताओं को संस्कारित करने का काम किया। उनका

एकात्म मानववाद का दर्शन न केवल भारत अपितु सम्पूर्ण विश्व की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को अक्षरशः चरितार्थ करने का काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत पर माँ भारती की सेवा में अहर्निश लगी हुई है। ■

भारत रत्न नानाजी देशमुख

- विकाश आनन्द

भारत रत्न नानाजी देशमुख का पूरा जीवन राष्ट्रोत्थान के लिए समर्पित रहा। बाल्यकाल से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सम्पर्क में आ गये थे। इनका जन्म तो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के कड़ोली में 11 अक्तूबर 1916 को हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि राजस्थान और उत्तर प्रदेश रही। जब वे राजस्थान के पिलानी स्थित बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी एंड सांइस में स्नातक करने गए, तो वहीं पढ़ाई के साथ–साथ राजस्थान में संघ कार्य में लग गए। लेकिन नानाजी अपना जीवन संघ के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करना चाहते थे। 24 वर्ष की आयु में अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आगरा चले गए। आगरा में कुछ दिन रहने के बाद उन्हें भाऊराव देवरस के पास कानपुर भेज दिया गया। भाऊराव ने उन्हें संघ कार्य शुरू करने के लिए गोरखपुर भेज दिया। 15 अगस्त 1940 को मात्र 14 रुपए के साथ गोरखपुर के लिए रवाना हो गए। गोरखपुर उनके लिए नई जगह थी। कोई परिचित नहीं था, लेकिन अपनी लगन और निष्ठा से तीन वर्ष में ही गोरखपुर शहर और शहर से बाहर लगभग 250 संघ शाखा खड़ी कर दी। शिक्षा से उनका लगाव था। इसलिए उन्होंने 1950 में गोरखपुर में देश का पहला सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की। बाद में संघ के सह प्रांत प्रचारक का भी दायित्व मिला। 1948 से 1952 तक वे राष्ट्रधर्म प्रकाशन के प्रबंध संपादक की भूमिका भी बहुत सफलतापूर्वक निभाई।

देवेन्द्र स्वरूप जी ने 'राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख' नामक पुस्तक में लिखा है कि नानाजी देशमुख 'राजनीति के बहिष्कार में नहीं परिष्कार' में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपने जीवन का तीन दशक सक्रिय राजनीति में बितायी। जब डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ बन रहा था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें दीनदयालजी और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनसंघ का संगठन मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश भेज दिया। अटलजी की भाषण कला और नानाजी देशमुख की संगठन क्षमता उत्तर प्रदेश में जनसंघ का विस्तार करने में काफी सहायक सिद्ध हुए। फिर इनके पूर्वी भारत के संगठन प्रभारी बना दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, बंगाल, असम आदि आते थे। नानाजी आपातकाल के खिलाफ जयप्रकाश आंदोलन के मुख्य रणनीतिकारों में एक थे। नानाजी के ही निवेदन पर चार विपक्षी दलों भारतीय लोकदल, कांग्रेस (संगठन), समाजवादी पार्टी और भारतीय जनसंघ ने संयुक्त रूप से अपनी कार्य समिति दिल्ली में की और आंदोलन के समन्वय के लिए 'लोक संघर्ष समिति' बनायी। इस समिति के महामंत्री का दायित्व नानाजी देशमुख को दिया गया। नानाजी ने 17 महीने आपातकाल में जेल में व्यतीत किए। जब आपातकाल हटाया गया, तब 'जनता सरकार' बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। जनसंघ का जनता पार्टी के विलय में नानाजी की प्रमुख भूमिका रही।

चूंकि ये बलरामपुर में लोकसभा का चुनाव जीते थे, इसलिए मोरारजी सरकार में इन्हें मंत्री पद दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे संगठन कार्य में ही लगे रहे। राजनीति के अलावा उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबी ग्राम निर्माण के क्षेत्र में भी कार्य किया। उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी भाग लिया। 60 साल की उम्र में वे संन्यास लेकर रचनात्मक कार्य में लग गए।

नानाजी ने जीवन के 34 साल रचनात्मक कार्य में लगाया। उन्होंने चित्रकूट के पिछड़े इलाकों के समग्र विकास में अपना जीवन खपाया। नानाजी ने वहां दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना की। देश में प्रथम ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में ही नानाजी देशमुख द्वारा किया गया और इसमे पहले कुलपति की भूमिका स्वयं निभायी। उन्होंने चित्रकूट में बहुत सारे प्रकल्पों जैसे आरोग्यधाम उद्यमिता विद्यापीठ, गौशाला, वनवासी छात्रवास, गुरुकुल, सुरेन्द्रपाल ग्रामोदय विद्यालय इत्यादि की स्थापना की। इस प्रकार राजनीति से संन्यास के बाद वे अपना शेष जीवन ग्रामीण क्षेत्र के विकास में बिताया। इन्होंने 500 गांवों को विकसित और सशक्त बनाया। समाज और देश के स्वार्थरहित सेवा के चलते इन्हें राष्ट्रऋषि कहा गया। 1999 में नानाजी को पद्मविभूषण और मरणोपरान्त 2019 में भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। 94 वर्ष की आयु में 27 फरवरी 2010 को चित्रकूट में इनका स्वर्गवास हो गया। ■

आर्थिक मोर्चे पर भारत का यह लाजवाब प्रदर्शन और सुनहरे भविष्य का संकेतः जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 23 फरवरी को कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के मामले में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। आर्थिक मोर्चे पर भारत का यह लाजवाब प्रदर्शन और सुनहरे भविष्य का संकेत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की आर्थिक सुधार की नीतियों व प्रभावी कार्यान्वयन का ही परिणाम है।

श्री नड्डा ने कहा कि इससे पहले 2018 में वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने फ्रांस को सातवें पायदान पर पीछे छोड़ते हुए छठा पायदान हासिल किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2019 में ब्रिटेन को पीछे धकेल कर भारत विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के 2018 वर्ल्ड इकॉनिक लीग टेबल ने भी जल्द ही भारत के पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित होने की भविष्यवाणी की थी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2024 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लिहाज से भारत का पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना प्रधानमंत्री जी के इस सपने को पूरा करने की दिशा में काफी अहम है। यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आंकड़े काफी मायने रखते हैं और ये आगे की दिशा और हमारी नीतियों को भी तय करने में मदद करते हैं। इसका निवेश में भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा।

उन्होंने कहा कि कई प्रतिष्ठित आर्थिक रेटिंग एजेंसियों ने माना है कि आत्मनिर्भर बनने की पहले की पॉलिसी से भारत अब आगे बढ़ गया है और वह एक ओपन मार्केट वाली अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप हो रहा है। हाल में ही अमेरिका के रिसर्च इंस्टीट्यूट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 2,940 अरब डॉलर को पार कर गई है। वर्तमान में ब्रिटेन का सकल घरेलू उत्पाद 2830 अरब डॉलर का है, जबकि फ्रांस की अर्थव्यवस्था का आकार 2710 अरब डॉलर का है। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर भारत की जीडीपी 10,510 अरब डॉलर है जो जापान और जर्मनी से भी ज्यादा है। हालांकि अधिक जनसंख्या के चलते भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी कुछ कम है। भारत ने क्रय शक्ति समानता में वृद्धि के साथ सभी क्षेत्रों में जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है जो कि सरकार के दूरदर्शी कदमों और विकासोन्मुखी बजट के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि विश्व की तमाम आर्थिक संगठनों की रिपोर्ट में अगले एक दशक में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर दिखाया गया है। लंदन स्थिति कंसल्टंसी फर्म 'सेंटर फॉर इकनॉमिक्स ऐंड बिजनस रिसर्च' ने भी कहा है कि जीडीपी के लिहाज से भारत ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को पीछे छोड़कर 2032 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। आईएमएफ का कहना है कि यदि भारत आर्थिक और कारोबार सुधारों की प्रक्रिया को वर्तमान की तरह निरंतर जारी रखता है तो वर्ष 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इसी तरह विश्वविख्यात ब्रिटिश ब्रोकरेज कंपनी हांगकांग एंड शंघाई बैंक कार्पोरेशन (एचएसबीसी) ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि अब भारत में आर्थिक सुधारों के कारण अर्थव्यवस्था का प्रभावी रूप दिखाई दे रहा है और वर्ष 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। शेयर बाजार ने 40,000 के लक्ष्यांक को पार कर लिया है। विदेशी मुद्रा भंडार अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर है और जीडीपी में प्रत्यक्ष कर का योगदान भी बढ़ा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2024 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है और इस लिहाज से भारत का पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनना प्रधानमंत्री जी के इस सपने को पूरा करने की दिशा में काफी अहम है।

उन्होंने कहा कि देश ने कांग्रेस की सरकार के समय एक दौर ऐसा भी देखा है, जब अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत को 'फ्रेजाइल फाइव' की श्रेणी में रखा गया था मतलब भारत के लिए खुद की अर्थव्यवस्था तो एक समस्या थी ही, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी बाधा बन रही थी। इसके ठीक विपरीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत पहली बार विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'मेक इन इंडिया' इनिशिएटिव के बल पर भारत अब विश्व का नया मैन्युफेक्चरिंग हब बनने की दिशा में भी तेज गति से अग्रसर है। प्रख्यात वैश्विक शोध संगठन स्टैटिस्टा और डालिया रिसर्च द्वारा मेड इन कंट्री इंडैक्स 2016 में उत्पादों की साख के अध्ययन के आधार पर कहा गया है कि गुणवत्ता के मामले में मेड इन इंडिया मेड इन चाइना से आगे है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार के अथक प्रयासों के कारण भारत निर्माण उद्योग के क्षेत्र में भी अच्छा कर रहा है। पिछले छः वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'न्यू इंडिया' की नींव रखने का काम किया है, ताकि भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन सके। ■

'शिरोमणि अकाली दल और भाजपा राजग को मजबूत करने में लगे हुए हैं'

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 20 फरवरी 2020 को पंजाब का प्रवास किया। उन्होंने अकाली दल के वरिष्ठ नेता एवं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल से उनके गांव में मुलाकात की। इसके बाद वह अमृतसर गए। श्री नड्डा के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ता उमड़ पड़े। रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह-जगह स्वागत किया। उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व भाजपा पंजाब प्रदेश प्रभारी श्री प्रभात झा एवं भाजपा पंजाब प्रदेश अध्यक्ष श्री अश्वनी शर्मा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता थे।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गुरुनगरी पहुंचे श्री नड्डा का भाजपा नेताओं ने गोल्डन गेट पर भव्य स्वागत किया। बारिश के बीच बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पमाला पहनाते हुए गुर्ज (गदा) भेंट किए। श्री नड्डा के स्वागत में विशेष रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री सर्व श्री अनिल जोशी, प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, राज्यसभा सदस्य श्वेत मलिक, केडी भंडारी, सुभाष शर्मा, रजिंदर मोहन सिंह छीना के अलावा बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे।

इससे पहले श्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात के बाद श्री नड्डा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बादलजी से उनका पुराना नाता है।

श्री बादल से मुलाकात के बाद श्री नड्डा शाम में अमृतसर पहुंचे। बारिश के मौसम के बावजूद भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और नड्डा का भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने गदा भेंटकर उनका स्वागत किया। श्री नड्डा ने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और पार्टी के लिए पूरी मेहनत से जुट जाने को कहा।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात करने के बाद श्री नड्डा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह आज प्रकाश सिंह बादल को अपने बेटे की शादी का निमंत्रण देने के लिए आए थे। जहां तक राजनीति का सवाल है तो शिरोमणि अकाली दल हमारा बहुत पुराना परखा हुआ सहयोगी है। शिरोमणि अकाली दल और भाजपा राजग को मजबूत करने में लगे हुए हैं।

श्री नड्डा ने कहा, 'प्रकाश सिंह बादल जी से मेरा आज का नहीं, बल्कि बहुत पुराना नाता है। जब मैं छात्र राजनीति में था तब से प्रकाश सिंह बादल जी का आशीर्वाद मुझ पर है। मैं आज उनसे यहां आशीर्वाद लेने आया था।

इससे पहले श्री नड्डा भटिंडा के भिसीआना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से मुक्तसर जिले के बादल गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते में उनका कई जगहों पर स्वागत किया गया। श्री नड्डा का एयरपोर्ट पर भटिंडा और फरीदकोट के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके बाद उनकागांव विर्क कलां, गांव बल्लूआना के पास और रिंग रोड पर भाजपा कार्यकताओं ने स्वागत किया। ■

मरांडीजी के भाजपा में आने से जन-कल्याण के लिए हमारी संघर्ष की ताकत कई गुनी बढ़ेगी: अमित शाह

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 17 फरवरी को रांची (झारखंड) के जगन्नाथपुर मैदान, धुर्वा में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में झारखंड विकास मोर्चा के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी ने अपने लाखों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पुनः ग्रहण की। श्री शाह ने बाबूलाल मरांडी को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इसके साथ ही झारखंड विकास मोर्चा का भी भारतीय जनता पार्टी में विधिवत विलय हो गया। जगन्नाथपुर मैदान में लाखों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता इस 'मिलन समारोह' के साक्षी रहे। कार्यक्रम को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री लक्ष्मण गिलुआ, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री करिया मुंडा, झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री श्री रघुबर दास, पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री अर्जुन मुंडा एवं श्री बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओम माथुर, भाजपा के प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री धर्मपाल सिंह, श्री रामविचार नेताम, झारखंड के सभी भाजपा सांसद, विधायक एवं पार्टी के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।

श्री शाह ने भाजपा में श्री बाबूलाल मरांडी का स्वागत करते हुए कहा कि मैं आज झारखंड आकर खुशी महसूस कर रहा हूं कि 14 वर्ष बाद श्री मरांडी कमल का निशान लेकर पार्टी में लौटे हैं, उनकी घर वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड की पावन धरा भगवान् बिरसा मुंडा की धरती है और हमारी सरकार ने सदैव ही आदिवासी शहीदों को पूरा सम्मान दिया है। जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण किया और हमें सरकार बनाने का अवसर मिला तो हमने एक आदिवासी शख्सियत श्री बाबूलाल मरांडी जी को प्रदेश का नेतृत्व सौंपा। उन्होंने कहा कि जब मैं 2014 में भाजपा अध्यक्ष बना था, उसी के बाद से बाबूलाल मरांडी जी को भाजपा में लाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज वे झारखंड के लोगों की इच्छा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि श्री मरांडी के भाजपा में आने से पार्टी की झारखंड के विकास एवं यहां की जनता के कल्याण के लिए संघर्ष की ताकत कई गुनी बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह कहा जा रहा है कि भाजपा झारखंड में चुनाव हार गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कभी भी चुनाव जीतना या हारना नहीं होता अपितु हमारा लक्ष्य तो प्रदेश और देश को आगे बढ़ाते हुए मां भारती को सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करने का होता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि झारखंड की नई सरकार यदि रघुबर सरकार की विकास की परंपरा को आगे बढ़ाती है, आदिवासियों, महिलाओं, दलितों और पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है, तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी से विकास कार्यक्रमों

के साथ दिखाई पड़ेगी लेकिन जिस तरह से पश्चिम सिंहभूमि जिले में सात लोगों की नृशंस हत्या की गई है, उसकी जितनी भी निंदा की जाय, वह कम है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की एक टीम जांच के लिए वहां गई थी, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है। मैंने वह रिपोर्ट देखी है। साथ ही नृशंस हत्या की तसवीरें भी मैंने देखी है। ऐसी नृशंस और निर्मम हत्या मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। निर्मम तरीके से सात लोगों की हत्या हुई, लेकिन झारखंड सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। यदि इसी तरह झारखंड में लचर कानून-व्यवस्था बनी रही, तो हम सड़क से लेकर सदन तक इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में श्री बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी में पुनः शामिल हुए हैं। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही आपको अपना ही मानती है और आज भी आपको अपना ही मानकर आपकी शक्तियों का महत्तम उपयोग झारखंड के हित में सुनिश्चित करेगी। मैं बाबूलाल जी के साथ आये हुए उनके लाखों कार्यकर्ताओं को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि केवल बाबूलाल मरांडी जी ही नहीं, आप सब भी भाजपा को अपना ही घर मान कर आये हैं। यहां भी आपके साथ अपने जैसा ही व्यवहार होगा। आपका भारतीय जनता पार्टी में उचित सम्मान भी होगा और आपको उचित जिम्मेवारी भी दी जायेगी।

इससे पहले 'मिलन समारोह' को संबोधित करते हुए श्री बाबूलाल मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का धन्यवाद किया। साथ ही, उपस्थित सभी लोगों के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी में मेरा जिस तरह से बाहें फैलाकर स्वागत किया गया है, उसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि आज मैं पार्टी में आया हूं तो किसी पद की लालसा में नहीं आया। मुझे पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा और एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। ■

विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) से 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निर्यात

विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) देश से निर्यात बढ़ाने में निरंतर अगुवाई कर रहे हैं। यहां तक कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज उतार-चढ़ाव के दौरान भी भारत में एसईजेड ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। एसईजेड से निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 17 फरवरी 2020 तक की अवधि में ही 100 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। उल्लेखनीय है कि एसईजेड से निर्यात ने 2018-19 के पूरे वित्त वर्ष में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को छूने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। 17 फरवरी तक वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2018-19 के आंकड़ों की तुलना नीचे दर्शाई गई है।

सर्विस सेगमेंट, जिसमें मुख्यतः आईटी एवं आईटी आधारित सेवाएं शामिल हैं, ने 23.69 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ निर्यात में प्रमुख योगदान दिया, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि दर रही। यह देश में एसईजेड के समग्र विस्तार और इनमें बढ़ती रुचि को दर्शाता है। यही नहीं, परिचालन कर रहे एसईजेड की संख्या भी बढ़कर 241 के स्तर पर पहुंच गई है, जबकि यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2018-19 के आखिर में 235 था।

चालू वित्त वर्ष में जिन महत्वपूर्ण सेक्टरों ने उल्लेखनीय वृद्धि दर दर्शाई है उनमें रत्न व जेवरात (13.3 प्रतिशत), व्यापार (ट्रेडिंग) एवं लॉजिस्टिक्स (35 प्रतिशत), चमड़ा व फुटवियर (15 प्रतिशत), गैर-परंपरागत ऊर्जा (47 प्रतिशत) और कपड़ा एवं परिधान (17.6 प्रतिशत) शामिल हैं। वैसे तो एसईजेड से कुल निर्यात में पेट्रो-रसायन का अहम योगदान होता है, लेकिन इस सेगमेंट में वृद्धि दर अपेक्षाकृत कम रही। ऐसा संभवतः कच्चे तेल (क्रूड) के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आने से हुआ है।

रुपये में निर्यात (करोड़ रुपये में)

निर्यात खंड	वित्त वर्ष 2019-20 (17 फरवरी तक)	वित्त वर्ष 2018-19 (17 फरवरी तक)	निर्यात मूल्य में वृद्धि (रुपये में)	निर्यात मूल्य में वृद्धि (प्रतिशत में)
वस्तुएं	2,97,557	2,86,553	11,004	3.84%
सेवाएं	4,04,264	3,26,825	77,439	23.69%
	7,01,821	6,13,378	88,443	14.42%

अमेरिकी डॉलर में निर्यात (मिलियन डॉलर में)

निर्यात खंड	वित्त वर्ष 2019-20 (17 फरवरी तक)	वित्त वर्ष 2018-19 (17 फरवरी तक)	निर्यात मूल्य में वृद्धि (अमेरिकी डॉलर में)	निर्यात मूल्य में वृद्धि (प्रतिशत में)
वस्तुएं	42,702	41,471	1,231	2.97%
सेवाएं	57,891	47,217	10,674	22.61%
	1,00,593	88,688	11,906	13.42%

मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम पर बिम्सटेक सम्मेलन संपन्न

मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम पर बिम्सटेक सम्मेलन 14 फरवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसने दो दिनों के व्यापक विचार-विमर्श के बाद भागीदार राष्ट्रों को अपने विचार साझा करने और इस क्षेत्र में मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। विश्व के दो प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र- गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल- की भौगोलिक निकटता के कारण बिम्सटेक के सभी भागीदार देशों के लिए स्थिति काफी जोखिमपूर्ण रहती है। भारत की स्थिति कहीं अधिक चिंताजनक है क्योंकि हम गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच स्थित हैं। पिछले कुछ वर्षों से अफगानिस्तान में अफीम की बम्पर फसल होने के कारण सभी बिम्सटेक देशों में हेरोइन की आपूर्ति में वृद्धि हुई है। कुछ बिम्सटेक देशों में बड़ी तादाद में मेथमफेटामाइन विनिर्माण संयंत्रों का होना भी चिंता की बात है। इन संयंत्रों में बड़ी मात्रा में मेथमफेटामाइन का विनिर्माण होता है जिसकी तस्करी सभी बिम्सटेक देशों में की जाती है। समुद्री मार्ग से मादक पदार्थों की तस्करी भी चिंता की बात है, क्योंकि वह सभी बिम्सटेक देशों को प्रभावित करती है। हाल में बंगाल की खाड़ी में दो जहाजों से भारतीय अधिकारियों द्वारा 371 किलोग्राम और 1156 किलोग्राम मेथमफेटामाइन की बरामदगी हुई जो इसके उल्लेखनीय उदाहरण हैं। ■

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-दो को मंजूरी

2020-21 से 2024-25 तक के लिए 1,40,881 करोड़ रुपये के परिव्यय

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के दूसरे चरण को 2024-25 तक के लिए मंजूरी दे दी। इसमें खुले में शौच से मुक्ति के बाद सार्वजनिक शौचालयों में बेहतर सुविधाओं (ओडीएफ प्लस) पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा, जिसमें खुले में शौच मुक्त अभियान को जारी रखना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) भी शामिल होगा।

इस कार्यक्रम में यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य किया जायेगा कि एक व्यक्ति भी न छूटे और हर व्यक्ति शौचालय का इस्तेमाल करे। एसबीएम (जी) चरण- दो को वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिए 1,40,881 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा।

यह वित्त पोषण के विभिन्न आयामों के बीच तालमेल का एक अच्छा मॉडल होगा। इसमें से 52,497 करोड़ रुपये पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजट में से आवंटित किए जाएंगे, जबकि शेष धनराशि को विशेष कर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15वें वित्त आयोग, मनरेगा और राजस्व सृजन मॉडलों के तहत जारी की जा रही धनराशियों से वित्त पोषित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार नये पात्र घरों को 12,000 रुपये की राशि प्रदान करने का प्रावधान जारी रहेगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) के लिए वित्त पोषण मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया गया है और घरों की संख्या को प्रति व्यक्ति आय से बदल दिया गया है।

इसके अलावा ग्राम पंचायतों (जीपी) को ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण (सीएमएससी) के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 2 लाख से 3 लाख रुपये कर दिया गया है। इस कार्यक्रम को परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जो शीघ्र ही राज्यों को जारी किए जाएंगे।

केन्द्र और राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए फंड शेयरिंग का ढांचा पूर्वोत्तर राज्यों एवं हिमालयी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के बीच 90:10, अन्य राज्यों के बीच 60:40 और अन्य केन्द्र शासित प्रदेश के बीच 100:0 होगा।

ओडीएफ प्लस के एसएलडब्ल्यूएम घटक की निगरानी चार प्रमुख क्षेत्रों के आउटपुट-आउटकम संकेतकों के आधार पर की

जाएगीः प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैव अपघटित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (जिसमें पशु अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है), धूसर जल प्रबंधन और मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन।

एसबीएम-जी का दूसरा चरण रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को घरेलू शौचालय एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के माध्यम से प्रोत्साहन देना जारी रखेगा। साथ ही, एसएलडब्ल्यूएम के लिए बुनियादी ढांचे जैसे कि खाद के गड्ढे, सोखने वाले गड्ढे, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, शोधन संयंत्र आदि।

देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 2 अक्टूबर 2014 को एसबीएम (जी) की शुरुआत के समय 38.7 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इस मिशन के शुरू होने से 10 करोड़ से ज्यादा व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया। परिमाणस्वरूप सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने स्वयं को 2 अक्टूबर 2019 को ओडीएफ घोषित किया।

हालांकि, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने सभी राज्यों को यह सलाह दी है कि वे इस बात की पुनः पुष्टि कर लें कि ऐसा कोई ग्रामीण घर न हो, जो शौचालय का उपयोग नहीं कर पा रहा हो और यह सुनिश्चित करने के दौरान अगर ऐसे किसी घर की पहचान होती है तो उसको व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए जरूरी सहायता प्रदान की जाये, ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी पीछे न छूटे।

एसबीएम-जी चरण दो के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन से ग्रामीण भारत को ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती का प्रभावी रूप से सामना करने और इससे देश में ग्रामीणों के स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार करने में मदद मिलेगी। ■

10,000 नए एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन हेतु 'कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन' को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 फरवरी को किसानों के लिए अर्थव्यवस्था के व्यापक लाभ को सुनिश्चित करने हेतु 2019-2022 से 2023-24 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान 10,000 नए एफपीओ के गठन को अपनी स्वीकृति दे दी। प्रत्येक एफपीओ के शुभारंभ वर्ष से पांच वर्षों तक के लिए सहायता जारी रखी जाएगी।

लाभ

छोटे और सीमांत किसानों के पास मूल्य संवर्द्धन सहित उत्पादन तकनीक, सेवाओं और विपणन को अपनाने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं होती है। एफपीओ के गठन के माध्यम से किसान सामूहिक रूप से अधिक सुदृढ़ होने के साथ-साथ अधिक आय अर्जित करने हेतु अर्थव्यवस्था के व्यापक स्तरों के लाभ के माध्यम से ऋण और बेहतर विपणन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पाद और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे।

योजना की संक्षिप्त जानकारी

- पांच वर्ष की अवधि (2019-2022 से 2023-24) के लिए 4496.00 करोड़ रुपए के कुल बजटीय प्रावधान के साथ 10,000 नए एफपीओ के गठन और संवर्द्धन के लिए 'कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना और संवर्द्धन' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक नवीन योजना, इसमें प्रत्येक एफपीओ को पांच वर्षों के लिए आवश्यक सहयोग देने के लिए 2024-25 से 2027-28 की अवधि के लिए 2369 करोड़ रुपये की प्रतिबद्ध देनदारी भी शामिल है।
- प्रारंभिक तौर पर एफपीओ के गठन और प्रोत्साहन के लिए तीन कार्यान्वयन एजेंसियां नामतः स्मॉल फारमर्स एग्री-बिजनेस कन्सोर्टियम (एसएफएसी), नेशनल कोओपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (एनएबीएआरडी) होंगी। राज्य भी अगर इच्छुक हों तो डीएसी एंड एफडब्ल्यू के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से एजेंसी को कार्यान्वित करने के लिए नामित कर सकते हैं।
- डीएसी एंड एफडब्ल्यू एजेंसियों को कार्यान्वित करने के लिए समूह/राज्यों का आबंटन करेगा, जो इसी क्रम में राज्यों में समूह आधारित व्यापारिक संगठन का गठन करेगा।
- एफपीओ को कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा राज्य/समूह स्तर पर जुड़े समूह आधारित व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से गठित और प्रोत्साहित किया जाएगा। सीबीबीओ में फसल कृषि कर्म, कृषि विपणन/मूल्य संवर्धन और संसाधन, सामाजिक संग्रहण, विधि और लेखा एवं सूचना प्रौद्योगिकी/एमआईएस जैसे क्षेत्रों से विशेषज्ञों की पांच श्रेणियां होगी। ये सीबीबीओ एफपीओ के संवर्धन की दिशा में आने वाले सभी मुद्दों के लिए एक पूर्ण ज्ञान मंच के रूप में होंगे।
- एकीकृत पोर्टल और सूचना प्रबंधन एवं निगरानी के माध्यम से समग्र परियोजना दिशा-निर्देश, डाटा-संग्रहण और रखरखाव जैसी सुविधा प्रदान करने के लिए एसएफएसी के स्तर पर एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए) होगी।
- प्रारंभ में मैदानी क्षेत्र में एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 300 और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 100 होगी। हालांकि डीएसी एंड एफडब्ल्यू केन्द्रीय कृषि मंत्री की स्वीकृति के साथ आवश्यकता और अनुभव के आधार पर न्यूनतम सदस्यों की संख्या में संशोधन कर सकता है।
- देश में आकांक्षापूर्ण जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक एफपीओ के साथ आकांक्षापूर्ण जिलों में एफपीओ के गठन को प्राथमिकता दी जाएगी।
- एफपीओ द्वारा विशेष और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 'एक जिला एक उत्पाद' समूह के अंतर्गत एफपीओ को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- एफपीओ के इक्विटी आधार को मजबूत करने के लिए इसमें इक्विटी अनुदान का भी एक प्रावधान होगा।
- डीएसी एंड एफडब्ल्यू और नाबार्ड के द्वारा समान योगदान के साथ नाबार्ड में 1,000 करोड़ रुपये तक का ऋण गारंटी कोष और डीएसी एंड एफडब्ल्यू और एनसीडीसी के द्वारा समान योगदान के साथ एनसीडीसी में 500 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी कोष होगा, ताकि एफपीओ को ऋण प्रदान करने के मामले में वित्तीय संस्थानों के जोखिम को न्यूनतम करते हुए एफपीओ को संस्थागत ऋण के निरंतर प्रवाह हेतु उपयुक्त ऋण गारंटी प्रदान की जा सके।

पृष्ठभूमि

किसानों की आय को दोगुना करने की रिपोर्ट में 2022 तक 7,000 एफपीओ के गठन की सिफारिश और 'किसानों की आय को दोगुना (डीएफआई)' करने पर बल दिया गया है। केन्द्रीय बजट 2019-20 में सरकार ने 10,000 नये एफपीओ के सृजन की घोषणा की थी कि आगे अगले पांच वर्षों में किसानों के लिए अर्थव्यवस्था के व्यापक लाभ को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए एक समर्पित सहायता और समग्र योजना के रूप में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को ईपीओ के लक्षित विकास और इसकी दीर्घकालिकता के लिए प्रस्तावित किया गया है। ■

भारतीयों ने महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों का खुले दिल से स्वागत किया: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 फरवरी को कहा कि 1.3 अरब भारतीयों ने तमाम आशंकाओं को दरकिनार कर अदालतों के हालिया मुश्किल फैसलों का खुले दिल से स्वागत किया है, जिसकी दुनियाभर में चर्चा हो रही है।

प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय में 'न्यायपालिका और बदलती दुनिया' विषय पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय न्यायपालिका सम्मेलन 2020 के उद्घाटन समारोह में अदालतों के हालिया मुश्किल फैसलों का जिक्र किया।

प्रधानमंत्री ने लैंगिग न्याय के संदर्भ में ट्रांसजेंडरों को लेकर कानून, 'तीन तलाक' और दिव्यांगों के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का कोई भी देश या समाज इसके बिना समग्र विकास को प्राप्त करने का दावा नहीं कर सकता।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सैन्य सेवाओं में महिलाओं को अधिकार देने और महिलाओं को 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए हैं। उन्होंने विकास और पारिस्थितिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए पर्यावरण न्यायशास्त्र को पुनर्परिभाषित करने में भारतीय न्यायपालिका की प्रशंसा की।

श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि यह अदालतों के प्रक्रियात्मक प्रबंधन में मदद करेगा और न्याय प्रणाली को काफी हद तक लाभान्वित करेगा। उन्होंने मानव बुद्धि के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मेल का भी उल्लेख किया और कहा कि यह न्याय दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाएगा।

श्री मोदी ने कहा, 'इसके अलावा, बदलते समय के साथ डेटा संरक्षण, साइबर-अपराध न्यायपालिका के सामने नयी चुनौतियां पेश कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'हाल ही में दिये गए कुछ महत्वपूर्ण अदालती फैसले वैश्विक चर्चा का विषय रहे हैं। यह फैसले आने से पहले इनके परिणामों को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही थीं। लेकिन देखिये क्या हुआ! 1.3 अरब भारतीयों ने उन अदालती फैसलों का खुले दिन से स्वागत किया।'

उन्होंने महात्मा गांधी के योगदान पर बात करते हुए कहा, 'गांधीजी का जीवन सत्य और सेवा के लिए समर्पित था, जो कि न्याय की किसी भी व्यवस्था के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं, वह स्वयं एक बैरिस्टर थे और वकीलों की बिरादरी के थे।

उन्होंने जीवंत न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को सलाम करते हुए कहा, 'संविधान के इन तीन स्तंभों ने एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र और गरिमा का सम्मान करते हुए, कई मौकों पर देश के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया है।'

उन्होंने कहा, 'हमें भारत में ऐसी समृद्ध परंपरा के विकसित होने पर गर्व है। पिछले पांच वर्षों में भारत के विभिन्न संस्थानों ने इस परंपरा को और मजबूत किया है।' उन्होंने 1,500 पुरातन कानूनों को निरस्त करने के केंद्र के प्रयास का जिक्र करते हुए कहा, 'न सिर्फ अप्रासंगिक कानूनों को खत्म करने, बल्कि सामाजिक तानेबाने को मजबूत करने के उद्देश्य से नए विधानों को लागू करने की गति भी बढ़ गई है।'

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान समानता के अधिकार के प्रावधानों के तहत लैंगिक न्याय की गारंटी देता है। उन्होंने कहा, 'भारत उन कुछ देशों में से एक है जिसने स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं का मताधिकार सुनिश्चित किया है।' उन्होंने अपनी सरकार के महत्वाकांक्षी 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम का भी जिक्र किया।

उन्होंने कहा, 'इसी तरह सरकार ने कई बदलाव किए हैं, चाहे वह सैन्य सेवा में महिलाओं की नियुक्ति हो या लड़ाकू पायलटों की चयन प्रक्रिया या रात में खदानों में काम करने की उनकी स्वतंत्रता के बारे में हो।'

इस मौके पर भारत के प्रधान न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का समागम है, जिसमें मुगलों, डच, पुर्तगालियों और अंग्रेजों की संस्कृतियां समाहित हैं। बोबडे ने कहा, 'संविधान ने एक मजबूत तथा स्वतंत्र न्यायपालिका का सृजन किया है और हमने इस मूलभूत विशेषता को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया है।

इससे पहले केन्द्रीय कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने उच्चतम न्यायालय के फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि आतंकवादियों और भ्रष्ट लोगों के लिये 'निजता का कोई अधिकार नहीं' है और ऐसे लोगों को व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करने देना चाहिये।

श्री प्रसाद ने कहा कि शासन की जिम्मेदारी निर्वाचित प्रतिनिधियों और निर्णय सुनाने का काम न्यायाधीशों पर पर छोड़ देना चाहिये। कानून मंत्री ने कहा कि लोकलुभावनवाद को कानून के तय सिद्धांतों से ऊपर नहीं होना चाहिये। ■

सरकार ने सैन्य सेवाओं में महिलाओं को अधिकार देने और महिलाओं को 26 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स

खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स में 80 में से 56 रिकॉर्ड हमारी बेटियों के नामः प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी को ओडिशा में वीडियो लिंक के माध्यम से पहले 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स' का उद्‌घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज केवल एक टूर्नामेंट की शुरुआत नहीं हो रही है, बल्कि यह भारत में खेल आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत है। यहां पर आप की प्रतिस्पर्धा न केवल एक-दूसरे के साथ हो रही हैं, बल्कि आप खुद के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "मैं प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप के साथ जुड़ रहा हूं, लेकिन वहां के उत्साह, जुनून और ऊर्जा के वातावरण की अनुभूति मैं प्राप्त कर सकता हूं। भारत के इतिहास में पहले 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स' की शुरुआत आज ओडिशा में हो रही है। यह भारत के खेल के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह भारत में खेलों के भविष्य के लिए भी एक बड़ा कदम है।"

पिछले 5-6 वर्षों में, भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने और उसमें भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। प्रतिभाओं की पहचान करने, प्रशिक्षण देने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा कि खेले इंडिया अभियान खेल के प्रति रुचि को बढ़ावा देने और देश के प्रत्येक कोने से युवा प्रतिभाओं की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2018 में जब खेले इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी, तब इसमें 3,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन मात्र तीन वर्षों में ही खिलाड़ियों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 6 हजार से ज्यादा हो चुकी है।

उन्होंने ने कहा, "इस वर्ष, खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स में 80 रिकॉर्ड तोड़े गए हैं, जिसमें से 56 रिकॉर्ड हमारी बेटियों के नाम हैं, हमारी बेटियों ने सफलता दर्ज की है, हमारी बेटियों ने चमत्कार दिखाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान के अंतर्गत आने वाली प्रतिभाएं बड़े शहर की नहीं, बल्कि छोटे शहरों की हैं।"

प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि पिछले 5-6 वर्षों में भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने और उसमें भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। प्रतिभाओं की पहचान करने, प्रशिक्षण देने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

श्री मोदी ने कहा, "ये वो खिलाड़ी हैं जिनका टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने की संभावना है। इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होने वाले खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, एशियाई पैरा खेलों, युवा ओलंपिक जैसे कई खेल आयोजनों में देश को 200 से ज्यादा पदक दिलवाए हैं। आने वाले दिनों में, 200 से ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने प्रदर्शन में सुधार करें और अपनी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं।" ■

धारा 371 को कोई हटा नहीं सकता, न ही ऐसी कोई मंशा है: अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश के 34वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरे देश में मेरा दौरा होता है, पर अरुणाचल अकेला ऐसा राज्य है जहां जय हिंद से एक दूसरे का स्वागत किया जाता है, देशभक्ति की ऐसी मिसाल देखकर हर्ष होता है। श्री शाह ने कहा कि 2014 से पहले उत्तर-पूर्व केवल भौगोलक रूप से देश के साथ जुड़ा था, पर श्री नरेंद्र मोदी ने इस हिस्से को सांस्कृतिक रूप से देश के साथ जोड़ा। पहले केवल सरकार बनाने के लिए नॉर्थ-ईस्ट की ओर देखा जाता था, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नॉर्थ-ईस्ट को विकसित क्षेत्र बनाने के लिए, नॉर्थ-ईस्ट को देश के सीमावर्ती क्षेत्र की अभेद दीवार बनाने के लिए और नॉर्थ-ईस्ट की संस्कृति को भारतीय संस्कृति का सौंदर्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन में पूर्वोत्तर राज्यों के लिये विशेष प्रेम है और राष्ट्र के इस महत्वपूर्ण भाग के स्थानों के महत्व को समझने के लिये हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सभी मंत्रियों को हर पखवाड़े में उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करने और क्षेत्र की समस्याओं को हल करने के लिए निर्देश दिए गए। श्री मोदी ने नॉर्थ-ईस्ट के जुड़ाव का जो कार्यक्रम चलाया है उसमें अरुणाचल प्रदेश का एक अलग स्थान है। यहां के जनजातियों की एक अलग विशेषता है और 27 जनजातियों और 120 उपजनजातियों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी परंपरा और संस्कृति की रक्षा करना भारत सरकार का दायित्व है और इसे कर्तव्य मानकर हम इस पर कार्य करते रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में डीडी चैनल शुरू किया गया। उनका कहना था कि एनईसी के तहत जारी होने वाले बजट का 33 परसेंट उन गांवों में खर्च किया जाएगा, जहां बिजली, गैस आदि मूलभूत सुविधाओं की कमी है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उनका कहना था कि पासीघाट और ईटानगर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कार्य किया जा रहा है।

श्री शाह ने बताया कि केन्द्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक की मंजूरी दी है और 700 किमी हाइ-वे निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। श्री शाह का कहना था कि नाहरलगुन में पहला रेलवे स्टेशन बनने के बाद अरुणाचल प्रदेश को देश के रेल मानचित्र में लाया गया। विभिन्न नई रेल लाइनों के अतिरिक्त 900 किमी के मीटरगेज रेलवे लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तित किया जा चुका है। रेल मंत्रालय राज्य में तीन रणनीतिक रेलवे लाइनों भालुकपोंग-तेंगा-तवांग, लिकाबाली से बेम और रुक्सिन तथा परशरमकुंड से होते तेजू और रुपाइ का सर्वेक्षण

और जांच कर रहा है।

उनका कहना था कि भारत सरकार ने देश के हवाई नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को लाने की दिशा में पासीघाट हवाई अड्डे का संचालन करने के अलावा, हालोंगोई हवाई अड्डे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है, जो पिछले 12 वर्षों से अटका हुआ था। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की कड़ी में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के जोत में नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्थायी कैंपस की स्थापना के लिए अनुमान की संशोधित लागत 430.56 करोड़ को मंजूरी दी।

श्री शाह ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी जिले परियोजना के अंतर्गत नैमसाई जिले के विकास में सराहनीय प्रदर्शन किया है और आज यह जिला दूसरे जिलों को लिये प्रेरणा देने का कार्य कर रहा है। नैमसाई जिले ने मार्च 2019 में डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा क्षेत्र में पहली रैंकिंग हासिल की। 19 स्वास्थ्य केंद्रों में से 18 को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के रूप में अपग्रेड किया गया है और विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं और जिले के लोगों तक विकासात्मक लाभ पहुंच सके इस दिशा में विशेष प्रयास किया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि धारा 370 हटाने के बाद पूरे नॉर्थ-ईस्ट में यह अफवाह फैलाई गई कि धारा 370 के साथ 371 से भी छेड़छाड़ की जाएगी, लेकिन मैं आज आश्वस्त करना चाहता हूं कि धारा 371 को कोई हटा नहीं सकता। इस तरह की अफवाह फैलाकर भारत और उत्तर-पूर्व के हिस्से के बीच में अंतर पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी कोशिश कभी सफल नहीं होगी। श्री अमित शाह ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी उत्तरपूर्व को समस्या मुक्त चाहते हैं और 2024 तक इसमें पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। श्री शाह ने कहा कि मैं आप लोगों को पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश राज्य के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ■

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत वितरित हो चुके हैं 50,850 करोड़ रुपये

भाजपानीत केंद्र की राजग सरकार ने 22 फरवरी को कहा कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के बीच अभी तक 50,850 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। इस योजना के 24 फरवरी को एक साल पूरे होने वाले हैं।

इस योजना का शुभारंभ देश भर के सभी खेतीहर किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करके किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, ताकि उनकी कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू व्यय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

इस योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि को 2000 रुपये की तीन मासिक किस्तों में प्रत्येक चौथे माह किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित किया जाता है। उच्च आय की स्थिति से संबंधित मामले अपवाद के रूप में कुछ मानदंडों के अधीन है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक भव्य समारोह के साथ किया था। यह योजना 01 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी है। पात्रता के संबंध में लाभार्थियों की पहचान के लिए समय सीमा तिथि 01 फरवरी, 2019 थी।

लाभार्थियों की पहचान का पूर्ण दायित्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों पर है। योजना के लिए एक विशेष वेब-पोर्टल www.pmkisan.gov.in प्रारंभ किया गया है। लाभार्थियों को वित्तीय लाभ पीएम-किसान वेब-पोर्टल पर उनके द्वारा तैयार और अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी किए जाते हैं।

इस योजना के तहत प्रारंभ में पूरे देश में 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि रखने वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान की गई। बाद में 01 जून 2019 से इसके दायरे को विस्तारित करते हुए देश के सभी खेतीहर किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया।

हालांकि पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर अदा करने वाले प्रभावशाली पेशेवर किसानों जैसे चिकित्सकों, अभियंताओं, अधिवक्ताओं, सनदी लेखाकारों और प्रति माह कम से कम 10,000 रुपये के पेंशनभोगियों (एमटीएस/चतुर्थ श्रेणी/ समूह घ कर्मचारी को छोड़कर) को इस योजना से बाहर रखा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जहां भूमि स्वामित्व के अधिकार समुदाय आधारित हैं, वन निवासी और झारखंड, जिनके पास भूमि के अद्यतन रिकॉर्ड और भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध नहीं है।

नामांकन के लिए किसान को राज्य सरकार द्वारा नामित स्थानीय

पटवारी/राजस्व अधिकारी/नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) से संपर्क करना होगा।

किसान पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से अपना स्व-पंजीकरण भी करा सकते हैं। पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने आधार डेटाबेस कार्ड के अनुसार पीएम-किसान डेटाबेस में अपने नाम में सुधार कर सकते हैं। पोर्टल में फारमर्स कॉर्नर के माध्यम से किसान अपने भुगतान की स्थिति भी जान सकते हैं। लाभार्थियों के ग्राम-वार विवरण भी फारमर्स कॉर्नर पर उपलब्ध हैं।

कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) को भी शुल्क के भुगतान पर योजना के लिए किसानों के पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। फारमर्स कॉर्नर पर दी गई उपरोक्त सुविधाएं सीएससी के माध्यम से भी उपलब्ध हैं। कृषि जनगणना 2015-16 के आधार पर इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या 14 करोड़ है।

पीएम-किसान पोर्टल में राज्य नोडल अधिकारी (एसएनओ) द्वारा पंजीकृत लाभार्थी 4 माह की अवधि से अपने लाभ के हकदार हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने स्थिति सत्यापन के लिए 24 घंटे 7 दिन कार्य करने वाली एक स्वचालित आईवीआरएस आधारित हेल्पलाइन का भी शुभारंभ किया है।

किसान अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए 1800-11-5526 या 155261 डायल कर सकते हैं। इसके अलावा, किसान अब ईमेल pmkisan-ict@gov.in पर पीएम किसान टीम से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकारें किसानों के लिए समय-समय पर शिविरों का भी आयोजन कर रही हैं, ताकि उनके आवेदन विवरणों में सुधार किया जा सके।

1 दिसंबर, 2019 को या उसके बाद मिलने वाली सभी किस्तों

20-02-2020 को पीएम-किसान के लाभार्थी	
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	किसानों/परिवारों की संख्या
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16,521
आंध्र प्रदेश	51,17,791
बिहार	53,60,396
चंडीगढ़	423
छत्तीसगढ़	18,80,822
दादरा और नगर हवेली	10,462
दमन और दीव	3,466
दिल्ली	12,896
गोवा	7,248
गुजरात	48,75,048
हरियाणा	14,55,118
हिमाचल प्रदेश	8,72,175
जम्मू और कश्मीर	9,34,299
झारखंड	14,36,023
कर्नाटक	49,12,445
केरल	27,73,306
लक्षद्वीप	-
मध्य प्रदेश	55,19,575
महाराष्ट्र	84,59,187
ओडिशा	36,28,657
पुडुचेरी	9,736
पंजाब	22,40,189
राजस्थान	52,04,520
तमिलनाडु	35,34,527
तेलंगाना	34,81,656
उत्तर प्रदेश	1,87,64,926
उत्तराखंड	7,01,855
पश्चिम बंगाल	--
कुल (1)	**8,12,13,267**
पूर्वोत्तर के राज्य	
अरुणाचल प्रदेश	50,823
असम	27,04,200
मणिपुर	1,73,789
मेघालय	70,236
मिजोरम	67,540
नगालैंड	1,70,334
सिक्किम	1,372
त्रिपुरा	1,96,767
कुल (2)	34,35,061
कुल योग (1+2)	**8,46,48,328**

का भुगतान लाभार्थियों को केवल आधार प्रमाणीकृत बैंक डेटा के आधार पर ही किया जा रहा है ताकि वास्तविक लाभार्थियों को सुनिश्चित करने के साथ-साथ दोहरे भुगतान से बचा जा सके। असम और मेघालय के अलावा केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को 31 मार्च 2020 तक इस आवश्यकता से छूट दी गई है।

केंद्र सरकार अब तक 50850 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी कर चुकी है। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुमानों के आधार पर योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 14 करोड़ है। 20 फरवरी, 2020 तक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा पीएम-किसान वेब पोर्टल पर अपलोड किए गए लाभार्थियों के आंकड़ों के आधार पर 8.46 करोड़ किसान परिवारों को लाभ दिया गया है। राज्यवार विवरण निम्न है:

इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक निगरानी तंत्र बनाया गया है। केंद्र के स्तर पर योजना में आवश्यक संशोधन के लिए केंद्रीय वित्त, कृषि और भूमि संसाधन मंत्रियों से युक्त एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

व्यय विभाग (डीईए), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू), भूमि संसाधन और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिवों के साथ कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर पर एक समीक्षा समिति समय-समय पर सदस्यों के रूप में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करती है।

संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तहत केन्द्रीय परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) इस योजना के कार्यान्वयन और प्रचार आदि की निगरानी करती है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के स्तर पर, नोडल विभाग और पीएमयू योजना के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करते हैं, जबकि राज्य और जिला स्तर की निगरानी समितियों का भी गठन किया गया है। ■

प्रधानमंत्री का हुनर हाट जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने का अनुरोध

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 फरवरी को 'मन की बात 2.0' की 9वीं कड़ी को संबोधित करते हुए दिल्ली में आयोजित हुनर हाट से संबंधित अपने दौरे का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले दिल्ली में हुनर हाट में मैंने एक छोटी सी जगह में हमारे देश की विशालता, संस्कृति, परम्पराओं, खानपान और जज्बातों की विविधताओं के दर्शन किये। वहां प्रदर्शित पारंपरिक वस्त्र, हस्तशिल्प, कालीन, बर्तन, बांस और पीतल के उत्पाद, पंजाब की फुलकारी, आंध्र प्रदेश के शानदार चमड़े के काम, तमिलनाडु की खूबसूरत चित्रकारी, उत्तर प्रदेश के पीतल के उत्पाद, भदोही की कालीन, कच्छ के तांबे के उत्पाद, अनेक संगीत वादय यंत्र, अनगिनत बातें, समूचे भारत की कला और संस्कृति की झलक वाकई अनोखी ही थी।"

प्रधानमंत्री ने हुनर हाट में भाग लेने वाले शिल्पकारों की प्रेरणादायी कहानियां भी साझा कीं। उनमें से एक कहानी एक दिव्यांग महिला की थी। प्रधानमंत्री ने कहा, "उन्होंने मुझे बताया कि पहले वह फुटपाथ पर अपनी पेंटिंग बेचती थी, लेकिन हुनर हाट से जुड़ने के बाद उनका जीवन बदल गया। आज वह न केवल आत्मनिर्भर है, बल्कि उन्होंने खुद का एक घर भी खरीद लिया है।"

उन्होंने कहा कि हुनर हाट कला के प्रदर्शन के लिए एक मंच तो है ही साथ-ही-साथ यह लोगों के सपनों को भी पंख दे रहा है। उन्होंने कहा, "यह एक ऐसी जगह है जहां इस देश की विविधता की अनदेखी करना असंभव ही है। यहां शिल्पकला के अलावा भारत के खान-पान की विविधता भी प्रदर्शित की गई है।"

प्रधानमंत्री ने जनता से ऐसे कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से भाग लेने का अनुरोध करते हुए कहा, "भारत के हर हिस्से में ऐसे मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहता है। जब भी मौका मिले भारत को जानने के लिए, भारत को अनुभव करने के लिए इनमें जरुर जाना चाहिए। इस तरह आप न सिर्फ देश की कला और संस्कृति से जुड़ेंगे, बल्कि आप देश के मेहनती कारीगरों, विशेषकर महिलाओं की समृद्धि में भी अपना योगदान दे सकेंगे।"

भारतीय युवाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि काफी बढ़ रही है

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे देश के युवाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा, "जब मैं चंद्रयान-2 के समय बेंगलुरु में था, तो मैंने देखा था कि वहां उपस्थित बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। नींद का नाम-ओ-निशान नहीं था। एक प्रकार से वे पूरी रात जागते रहे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को लेकर उनमें जो उत्सुकता थी, वो कभी हम भूल नहीं सकते हैं।"

'मन की बात' में आज इन विचारों को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों और युवाओं के इसी उत्साह को बढ़ाने के लिए तथा उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में श्रीहरिकोटा से होने वाले रॉकेट लॉचिंग को देखने के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई है। यह सुविधा सभी के लिए है और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। उन्होंने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और शिक्षकों से आने वाले समय में इस सुविधा का अवश्य लाभ उठाने का आग्रह किया।

इस संदर्भ में उन्होंने युवाओं को विज्ञान से जोड़ने के लिए इसरो के 'युविका' कार्यक्रम की सराहना की। 'युविका' का मतलब- 'युवा विज्ञानी कार्यक्रम' है। यह कार्यक्रम 2019 में स्कूली छात्रों के लिए आरंभ किया गया था। यह कार्यक्रम हमारे विजन, 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान' के अनुरूप है।

प्रधानमंत्री ने जैव-ईंधन से विमान उड़ाने की तकनीक को संभव बनाने के लिए सीएसआईआर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, देहरादून के वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन वैज्ञानिकों के प्रयासों से 'मेक इन इंडिया' मिशन को भी मजबूती मिली है।

उन्होंने कहा लेह के कुशोक बाकुला रिम्पोछे एयरपोर्ट से जब 10 प्रतिशत इंडियन बायो-जेट ईंधन के मिश्रण के साथ भारतीय वायुसेना के एएन-32 विमान ने उड़ान भरी, तो एक नया इतिहास बन गया और ऐसा पहली बार हुआ जब दोनों इंजनों में इस मिश्रण का इस्तेमाल किया गया।

उन्होंने कहा कि इस बायो-जेट ईंधन को नॉन-एडिबल ट्री बोर्न ऑयल से तैयार किया गया है। इसे भारत के विभिन्न आदिवासी इलाकों से खरीदा जाता है। इन प्रयासों से न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि कच्चे-तेल के आयात पर भी भारत की निर्भरता कम हो सकती है।

भारत पूरे साल कई प्रवासी प्रजातियों का आशियाना बना रहता है

'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है, जो शिक्षा और दीक्षा हमें मिली है। प्रत्येक प्राणी के प्रति दया का भाव, प्रकृति के प्रति अपार प्रेम, ये सारी बातें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अंग हैं।

प्रवासी पक्षियों के लिए टिकाऊ पर्यावास का निर्माण करने के भारत के प्रयासों, जिनकी हाल ही में गांधीनगर में सम्पन्न 'सीओपी-13 सम्मेलन' काफी सराहना की गई थी, का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत पूरे साल कई प्रवासी प्रजातियों का आशियाना बना रहता है। अलग-अलग इलाकों से पांच-सौ से भी ज्यादा किस्म के पक्षी यहां आते हैं।"

उन्होंने कहा कि आने वाले तीन वर्षों तक भारत प्रवासी प्रजातियों पर होने वाले 'सीओपी सम्मेलन' की अध्यक्षता करेगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इन प्रयासों के बारे में जनता अपने सुझाव जरुर भेजें। उन्होंने मेघालय में पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजाति की मछली का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, ''हमारे आस-पास ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं, जिनका अब तक पता नहीं लगाया गया हैं। इन अजूबों का पता लगाने के लिए खोजी जुनून जरुरी होता है।"

उन्होंने महान तमिल कवयित्री अव्वैयार को उद्धृत करते हुए कहा, "कट्टत केमांवु कल्लादरु उडगड़वु, कड्डत कयिमन अड़वा कल्लादर ओलाआडू।" इसका अर्थ है कि हम जो जानते हैं, वह महज़, मुट्ठी-भर रेत के समान है, लेकिन जो हम नहीं जानते हैं, वह अपने आप में पूरे ब्रह्माण्ड के समान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश की विविधता के साथ भी ऐसा ही है जितना जाने उतना ही कम है। उन्होंने कहा कि हमारी जैव विविधता पूरी मानवता के लिए अनोखा खजाना है जिसे हमें संजोना है, संरक्षित रखना है।

महा–शिवरात्रि के पर्व के लिए राष्ट्र को शुभकामना

प्रधानमंत्री ने हाल ही में देशभर में मनाए गए महा-शिवरात्रि के पर्व के लिए राष्ट्र को शुभकामनाएं अर्पित कीं। उन्होंने कहा 'महा-शिवरात्रि पर भोले बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे...आपकी हर मनोकामना शिवजी पूरी करें...आप ऊर्जावान रहें, स्वस्थ रहें... और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें।'

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आने वाले दिनों में होली का भी त्योहार है और इसके तुरंत बाद गुड़ी-पड़वा भी आने वाला है। नवरात्रि का पर्व भी इसके साथ जुड़ा होता है। राम-नवमी का पर्व भी मनाया जाएगा। पर्व और त्योहार, हमारे देश में सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हर त्योहार के पीछे कोई-न-कोई ऐसा सामाजिक संदेश छुपा होता है जो समाज को ही नहीं, पूरे देश को एकता में बांधकर रखता है।'

साथ ही, श्री मोदी ने बिहार की एक छोटी प्रेरणादायी कहानी का उल्लेख किया जो देश-भर के लोगों को प्रेरणा से भर देने वाली है। ये वो इलाका है जो दशकों से बाढ़ की त्रासदी से जूझता रहा है। ऐसे में, यहां, खेती और आय के अन्य संसाधनों को जुटाना बहुत मुश्किल रहा है। मगर इन्हीं परिस्थितियों में पूर्णिया की कुछ महिलाओं ने एक अलग रास्ता चुना।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'पहले इस इलाके की महिलाएं, शहतूत या मलबरी के पेड़ पर रेशम के कीड़ों से कोकून तैयार करती थीं। जिसका उन्हें बहुत मामूली दाम मिलता था। जबकि उसे खरीदने वाले लोग, इन्हीं कोकून से रेशम का धागा बनाकर मोटा मुनाफा कमाते थे। लेकिन, आज पूर्णिया की महिलाओं ने एक नई शुरुआत की और पूरी तस्वीर ही बदलकर के रख दी। इन महिलाओं ने सरकार के सहयोग से, सहयोग से उत्पादन सहकारी संघों का निर्माण किया, रेशम के धागे तैयार किये और फिर उन धागों से खुद ही साड़ियां बनवाना भी शुरू कर दिया और अब बड़ी धनराशि अर्जित कर रही हैं। ■

उत्तर प्रदेश बजट 2020

अयोध्या में बनेगा विश्वस्तरीय एयरपोर्ट

500 करोड़ रुपये मंजूर

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भगवान राम की नगरी अयोध्या को 18 फरवरी को बड़ा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने अयोध्या में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एयरपोर्ट बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किया। यूपी सरकार ने 18 फरवरी को अपना बजट पेश किया। वहीं, सरकार ने जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये आवंटित किए।

पिछले साल के यूपी के बजट में भी अयोध्या एयरपोर्ट को 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार अयोध्या में विश्वस्तरीय एयरपोर्ट बनाने पर खास जोर दे रही है। यही वजह है कि हवाई अड्डे के लिए आवंटन काफी बढ़ाया गया है।

यह योगी सरकार का चौथा बजट है। बजट आकलन के अनुसार कुल प्राप्तियां 5,00,558.53 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। कुल व्यय 5,12,860.72 करोड़ रुपये अनुमानित है। ■

'हुनर हाट' देखने पहुंचे प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 फरवरी को नई दिल्ली के इंडिया गेट लॉन में आयोजित 'हुनर हाट' को देखने गए। उन्होंने हुनर हाट में देशभर से भाग ले रहे उस्ताद शिल्पकारों, दस्तकारों तथा व्यंजन विशेषज्ञों के स्टॉल देखे। इंडिया गेट लॉन में 250 से अधिक ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं। हुनर हाट में भाग ले रहे शिल्पकारों में 50 प्रतिशत से अधिक महिला शिल्पकार हैं। प्रधानमंत्री ने दस्ताकारों के साथ बातचीत की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा।

हुनर हाट रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सरकार के संकल्प के साथ-साथ भारत की स्वदेशी परम्पराओं के संरक्षण और प्रोत्साहन को दिखाता है। इनमें से कई परम्पराएं विलुप्त हो रही हैं।

इस वर्ष के हुनर हाट का विषय 'कौशल को काम' है। पिछले तीन वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग 3 लाख उस्ताद शिल्पकारों, दस्तकारों और व्यंजन विशेषज्ञों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए है। लाभार्थियों में बड़ी संख्या में महिला शिल्पकार शामिल हैं। ■

राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से की मुलाक़ात और अयोध्या आने का दिया निमंत्रण

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रबंध महंत नृत्य गोपाल दास समेत ट्रस्ट के सदस्यों ने 20 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण दिया।

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हाल ही में गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक 19 फरवरी को हुई थी। ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद नेता श्री चंपत राय तथा कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि भी बैठक में उपस्थित थे।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के पिछले साल 9 नवंबर को दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया था। फैसले में विवादास्पद स्थल पर मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई थी। ट्रस्ट के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में की थी।

मुलाकात के बाद महंत नृत्य गोपाल दास ने संवाददाताओं से कहा, 'हमने प्रधानमंत्री को अयोध्या आने (भूमिपूजन के लिए) का निमंत्रण दिया।' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनको बताया कि वह इस पर विचार करेंगे। ट्रस्ट द्वारा भूमिपूजन की तारीख अभी तय किया जाना बाकी है, लेकिन इसके अगले कुछ महीनों में होने की संभावना है।

बाद में श्री राय ने बताया कि न्यासी प्रधानमंत्री श्री मोदी से मिले और यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी।

न्यास की दिल्ली में 19 फरवरी को हुई बैठक में महंत नृत्य गोपालदास को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का 'अध्यक्ष प्रबंध', विहिप के चंपत राय को महासचिव एवं पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह श्री नृपेन्द्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया गया। स्वामी गोविंददेव गिरि जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अयोध्या में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में न्यास का बैंक खाता खोलने का निर्णय किया गया।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के पिछले साल 9 नवंबर को दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया था। फैसले में विवादास्पद स्थल पर मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई थी। ट्रस्ट के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में की थी। ■

'महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय प्रगतिशील, ऐतिहासिक और शानदार'

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं लोक सभा सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 17 फरवरी को पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और कहा कि महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐतिहासिक है।

श्रीमती लेखी ने कहा कि महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन देने की मांग 17 सालों से चली आ रही थी। अदालत में भी यह मामला लगभग 10 वर्षों से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय हर लिहाज से एक अच्छा फैसला है। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन देने की दिशा में व्यापक कदम उठाये और आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय महिलाओं के पक्ष में आया। मैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने महिलाओं की सेना में परमानेंट कमीशन की मांग को पूरा करते हुए ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। मैं इस मामले से जुड़े पूर्व जजों जस्टिस कौल और जस्टिस एम सी गर्म को भी धन्यवाद करती हूं। इस मामले में कई पुरुष अधिकारियों ने भी मदद की और जो भी लोग इस न्यायिक प्रक्रिया में शामिल रहे, मैं उनका आज धन्यवाद करना चाहती हूं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सेना में स्थाई कमीशन पाने की महिलाओं की मांग पर दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला 2003 से चल रहा था। इसके बाद 2009 तक 9 महिला अफसरों ने हाईकोर्ट में इसी मुद्दे पर अलग-अलग याचिकाएं दायर कीं। 12 मार्च 2010 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाया और महिलाओं को सेना में स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की यूपीए सरकार ने हाई कोर्ट के इस निर्णय को जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तब कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ अपनी दलील में कहा था कि सेना में ज्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जवान महिला अधिकारियों से कमांड लेने को लेकर बहुत सहज नजर नहीं आते। महिलाओं की शारीरिक स्थिति, परिवारिक दायित्व जैसी बहुत सी बातें उन्हें कमांडिंग अफसर बनाने में बाधक हैं। ■

कमल संदेश के आजीवन सदस्य बने

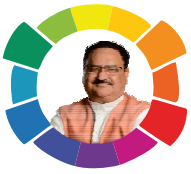

आज ही लीजिए कमल संदेश की सदस्यता और दीजिए राष्ट्रीय विचार के संवर्धन में अपना योगदान!

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चेक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चेक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें

डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003

फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

तीन ज्योतिर्लिंग– काशी, महाकाल, ओंकारेश्वर को जोड़नेवाली महाकाल एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और साथ में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य

नई दिल्ली में आयोजित हुनर हाट में लोकप्रिय बिहारी व्यंजन लिट्टी–चोखा खाते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाने हेतु अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी को चादर देने के बाद नई दिल्ली में एक ग्रुप फोटो में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में पुर्तगाल के राष्ट्रपति श्री मार्सेलो रेबेलो डी सूसा से मिलते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री महिंदा राजपक्षे के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध

लॉग इन करें:

www.kamalsandesh.org

राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh

@KamalSandesh

kamal.sandesh

KamalSandeshLive

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2018-20
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2018-20